

RNI No.DELHIN/2011/41355

दिल्ली से प्रकाशित

जनवरी 2026 वर्ष 15 अंक 170 मूल्य ₹20

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति बीएसपी और अपराध पर केंद्रित पत्रिका



अलविदा
2025

PRIME INDIA
MEDIA HOUSE



PRIME CRIME INDIA

www.primecrimeindia.com

**PSU
TODAY**



NETA INDIA

राजनीति बीएसपी और अपराध पर केंद्रित पत्रिका

www.netaindia.com

Helping the future bloom



Rourkela



Durgapur



Bhilai

Social welfare and community development is at the core of NSPCL's Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD) philosophy and continues to be a top priority for the company. One of the ways in which the next generation, especially those belonging to the lesser privileged sections of society, is empowered is by helping them realize their dreams through education and training.



NTPC-SAIL Power Company Limited

(A Joint Venture of NTPC and SAIL)

Regd. Office:- 4th Floor, NBCC Tower 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066



नासिर खान
संपादक

आम लोगों को पूरा मौका मिले

यूपी में स्पेशल इंटेशिव रिविजन (SIR) का ड्राफ्ट रोल जारी हो गया है, जिसमें 2.89 करोड़ नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने नामों को काटने की वजहें बताई हैं, लेकिन लोगों को दावे-आपत्तियों के लिए सरल प्रक्रिया की आवश्यकता है। बिहार में SIR को अंजाम दिया गया था। वहां जारी शुरुआती लिस्ट में 65 लाख नाम कटे थे। कई राजनीतिक विवाद और तारीखें बढ़ने के बाद आखिरकार यूपी में एसआईआर का ड्राफ्ट रोल जारी हो गया। चुनाव आयोग ने बताया है कि पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ नाम काटे गए हैं इसका अंदाजा पहले से ही था। अभी तक जिन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट लिस्ट आई है, वहां कुल मिलाकर 3.69 करोड़ नाम कटे हैं। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल नहीं होती। लोगों के पास दावे और आपत्तियों के लिए अब भी मौका है, लेकिन यह प्रक्रिया सरल और आम नागरिकों की सुविधा का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए।

बिहार में SIR को अंजाम दिया गया था। वहां जारी शुरुआती लिस्ट में 65 लाख नाम कटे थे, जिसे लेकर काफी हंगामा मचा था। जब लिस्ट रिवाइज की गई, तो 17.9 लाख वोटर्स और बढ़ गए। ऐसा ही बदलाव यूपी और उन राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जहां आपत्तियां ली जा रही हैं या अब ली जाएंगी। दूसरे चरण में जिन राज्यों में ड्राफ्ट रोल आ चुका है, वहां भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। खासकर बंगाल में सबसे ज्यादा असंतोष है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब SIR में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर पर सवाल उठाए हैं। उनकी पार्टी जडू उन वोटर्स की मैपिंग में भी गड़बड़ी बता रही है, जिनके नाम लिस्ट में नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर बताया है कि इन नामों को किन-किन वजहों से काटा गया। यह स्पष्टीकरण अच्छी बात है, लेकिन जिनके नाम नहीं हैं, उन्हें उनके मताधिकार को हासिल करने के लिए हरसंभव मदद की जानी चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे दावे-आपत्तियां दाखिल कराने, नाम चेक करने में आम लोगों की मदद करें। बिहार SIR से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर हैरानी जताई थी और पूछा था कि पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं व जनता के बीच इतनी दूरी क्यों है। लगभग 21 साल पहले हुए SIR की यादें भी अब धुंधली हैं, क्योंकि तब इतना शोर नहीं मचा था। शायद इसकी वजह बदली राजनीतिक परिस्थितियां हैं। अब यह शोर चुनावी उत्सव पर भारी न पड़े, जनता का सिस्टम पर से भरोसा न कम हो — इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है।

Goodbye
2025

Welcome
2026

वर्ष 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तौर पर रहा बेहद सफल-7

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

RNI No.DELHIIN/2011/41355

DAVP No.0813F27125-025

वर्ष-15, अंक: 170, जनवरी 2026

मूल्य ₹ 20

विदेश प्रतिनिधि

विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख

सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख

अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

श्वेतांक वर्मा

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

संजय सिन्हा

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

सुनील नेगी

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख

शाहिद अस्करी

दक्षिणांचल ब्यूरो

इमरान खान (वरिष्ठ संवाददाता)

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख

योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख

शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख

साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

रानू पाठक

पश्चिम बंगाल, दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी

नरेश कुमार श्रीवास्तव

विशेष संवाददाता

गुफरान खान

प्रमुख संवाददाता

गुलशन अरोड़ा

संपादक

नासिर खान

सलाहकार संपादक

राकेश त्रिपाठी

डॉ. ईशा

अर्चना ज्योती

राजनीतिक संपादक

इंजी.ए पी सिंह

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)

प्रशांत दत्त मिश्रा

कानूनी सलाहकार

डी.बी.गोस्वामी, सलीम खान

(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव

समीर अख्तर

उत्तराखंड में नस्लीय टिप्पणी के विरोध पर
त्रिपुरा के छात्र की हत्या 23

पीएसयू की खबरें 26

शामली में खौफनाक तिहरे हत्याकांड ने
इंसानियत को कर दिया शर्मसार 32

बचकर रहें ठंड में लकवा से 44

भारत ने स्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतकर
रचा इतिहास 47

फिल्मों में एंग्री मेन, पर्दे से क्यों लापता
लेडीज 49

उत्तर भारत की प्राचीन 'ग्रीन बॉल' पर क्यों छिड़ा है संग्राम-17



कोल इंडिया को बीसीसीएल आईपीओ में 10 फीसदी हिस्सेदारी से कमाएगी
600 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट-26

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो

मोहम्मद आसिफ (वरिष्ठ संवाददाता)

मथुरा ब्यूरो

विनय चौधरी (संवाददाता)

कानपुर ब्यूरो

अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)

बलिया ब्यूरो

डॉ. कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता),

आरा ब्यूरो

विमलेश कुमार (संवाददाता)

हाजीपुर ब्यूरो

राहुल कुमार (संवाददाता)

कार्यालय

कॉरपोरेट ऑफिस

91, फर्स्ट फ्लोर जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर,

दिल्ली- 110092

संपादकीय कार्यालय

आर-141/3 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092

मोबाइल-9718647540 Ph. 011-46536014

ईमेल-primespectator@gmail.com, primeindia-

mediahouse@gmail.com

वेबसाइट-primeindiamediahouse.com

primecrimeindia.com & netaindia.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा

ANEJA PRINTERS, C-11, SECTOR-10, NOIDA (UP) से प्रकाशित।

मुद्रित तथा आर-141/3 रमेश पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित।

सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टोर के किसी भी रचना के प्रकाशन

से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखक के

निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।



अलविदा 2025

वर्ष 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तौर पर रहा बेहद सफल



संजय सिन्हा
हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

वर्ष 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तौर पर बेहद सफल रहा। दिल्ली और बिहार में बड़ी जीत के साथ पार्टी ने न सिर्फ अपना दबदबा कायम रखा, बल्कि सहयोगी दलों को साथ साधने और राजनीतिक नैरेटिव तय करने की अपनी क्षमता भी दिखाई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष की मजबूत भूमिका में साल 2025 में पीछे नहीं रही। इसी साल बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हुई। कांग्रेस ने इसे लेकर श्वोट चोरी का आरोप लगाते हुए अभियान चलाया, और बाद में चुनाव आयोग ने देश के बड़े हिस्से में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू

कर दी। अब नजर अगले साल होने वाले चुनावों पर है। असम, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं।

लेकिन जब भारत की राजनीति भी 2026 में प्रवेश कर रही है तो इस साल भाजपा के सामने कई अहम चुनौतियां खड़ी होती दिख रही हैं। 2025 खत्म होकर नए साल 2026 का आगाज हो गया है। बीता पूरा साल राजनीतिक उठापटक से भरा रहा। साल की शुरुआत में जहां दिल्ली में चुनाव हुए तो अंत में बिहार के विधानसभा चुनाव। दिल्ली और बिहार दोनों जगह भाजपा ने अपनी सत्ता कायम की। दिल्ली में जहां 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी तो वहीं, बिहार में भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार ने फिर से सीएम पद की शपथ ली। ऐसे में कह सकते हैं कि वर्ष 2025 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चुनावी तौर पर बेहद सफल रहा। पार्टी ने बीते साल

न सिर्फ अपना दबदबा कायम रखा, बल्कि सहयोगी दलों को साथ साधने और राजनीतिक नैरेटिव तय करने की अपनी क्षमता भी दिखाई। साथ ही भाजपा यह संदेश देने में सफल रही कि नरेंद्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी अब भी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली जोड़ी है। अब इस नए साल के आगाज के साथ ही एक बार फिर कई राज्यों में विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा। 2025 की तुलना में इस साल चुनावी पारा ज्यादा हाई रहने वाला है। इस साल चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। इसके अलावा, राज्यसभा की भी 73 सीटें रिक्त हो रही हैं। वहीं, साल की शुरुआत में ही बीएमसी का चुनाव है। ऐसे में भाजपा के सामने कई चुनौतियां हैं। आइए जानते हैं कि इस साल किन-किन राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों में वर्तमान समीकरण कैसे हैं? साथ ही यह भी कि क्या इस बार दक्षिण में भाजपा संघ लगा पाएगी?



भाजपा के लिए कैसा रहा साल 2025

साल 2025 भारतीय राजनीति में भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस साल पार्टी ने न सिर्फ सत्ता और संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि विपक्ष की राजनीतिक रणनीतियों को भी कई मोर्चों पर ध्वस्त कर दिया। साल की शुरुआत भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद सत्ता में वापसी के साथ की। 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर पार्टी ने यह दिखा दिया कि शहरी राजनीति में उसका प्रभाव अब भी बरकरार है। यह जीत इसलिए भी अहम रही क्योंकि 'मोदी लहर' के दौर में भी भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई थी। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा नीत एनडीए के लिए प्रचंड जनादेश लेकर आए। अक्टूबर-नवंबर में हुए चुनावों में भाजपा को 89 और जदयू को 85 सीटें मिलीं। सहयोगी दलों के साथ एनडीए ने 200 से अधिक सीटों का आंकड़ा पार कर 2010 के बाद वैसा ही दबदबा दोहराया। वहीं, साल के आखिर में केरल के स्थानीय निकाय चुनाव खासकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसे दक्षिण भारत में भाजपा के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत ने संसद के भीतर गठबंधन की मजबूती भी साबित की।

2025 में इस रणनीति का मिला फायदा

2025 में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत रही उसका संगठनात्मक ढांचा। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पार्टी की चुन-चुनी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय रही। केंद्र में

मजबूत सरकार, राज्यों में सहयोगी दलों के साथ संतुलन और विपक्ष की बिखरी हुई रणनीति, इन सबका फायदा भाजपा को मिला। पीएम मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चुनावी रणनीति का भी फायदा पार्टी को मिला।

2026 में कहां कौन से चुनाव, अब बात इसकी

इस साल चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी हैं। इसके अलावा, राज्यसभा में भी 73 सीटें रिक्त हो रही हैं। चुनावी राज्यों में अधिकांश दक्षिण भारत के हैं। जिनमें पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है। केंद्रीय गृहमंत्री और आधुनिक भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बंगाल के लिए दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। इसके अलावा, इसी महीने महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव होने हैं।



जिनमें बीएमसी का चुनाव सबसे अहम है। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं, 2026 में राज्यसभा में भी कुल 73 सीटें खाली हो रही हैं। हालांकि इनके रिक्त होने का समय अलग अलग है। जैसे 37 सदस्य अप्रैल महीने में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं, जून में 22, नवंबर महीने में 11 सांसद रिटायर होंगे। इनके अलावा, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और मिजोरम से एमएएफ के सांसद के. वनलालवेना भी इसी साल अपना राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं झारखंड से राज्यसभा सांसद रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण खाली हुई सीट पर भी इसी साल चुनाव कराया जाना है।

कई उपचुनाव भी

इसके अलावा, इस साल कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाने हैं। इनमें गोवा में पोंडा, कर्नाटक में बागलकोट, महाराष्ट्र में राहुरी, मणिपुर में ताडुबी, और नागालैंड में कोरिडांग सीट शामिल हैं। ये सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट भी हाजी नूरुल इस्माल के निधन के कारण खाली हुई है। इस्लाम यहां से टीएमसी सांसद थे। यहां भी चुनाव होना है।

किस चुनावी राज्य में कैसे समीकरण

पश्चिम बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के संभावित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में मार्च से मई 2026 के बीच विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। 294 सदस्यीय विधानसभा वाले इस राज्य में मुकाबला एक बार फिर बेहद दिलचस्प होने वाला है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने जबरदस्त



प्रदर्शन करते हुए 215 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी को करीब 48 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल के रूप में खुद को स्थापित किया था। लगभग 38 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भाजपा का यह प्रदर्शन इसलिए भी अहम माना गया, क्योंकि 2016 के चुनाव में पार्टी केवल तीन सीटों तक सिमट गई थी।

2026 में होगी भाजपा की असली अग्निपरीक्षा

आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर पार्टी की मंशा और आक्रामक रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। भाजपा का फोकस सीधे सत्ता परिवर्तन पर है। इस बाबत भाजपा चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर हमला करने की तैयारी में है। पार्टी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, कानून-व्यवस्था की स्थिति और बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल भाजपा के चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा रहेंगे। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस की जमीनी पकड़ अब भी बेहद मजबूत है। संग. ठन, कैंडर और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे टीएमसी राज्य के बड़े हिस्से में प्रभावी बनी हुई है। ऐसे में 2026 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा।

तमिलनाडु में 2026 में त्रिकोणीय

मुकाबले के संकेत

इस साल दक्षिण के तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होना है। फिलहाल यहां द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 10 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में डीएमके के पाले में 133 सीटें आई थी। वहीं, उसके सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर ये आंकड़ा 159 हो गया था। वहीं, विपक्षी भाजपा, एआईएडीएमके और अन्य दलों के गठबंधन को कुल 75 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस साल का विधानसभा चुनाव डीएमके के लिए आसान नहीं माना जा रहा। सत्ता में रहते हुए पार्टी को एंटी-इनकंबेंसी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, जयललिता के निधन के बाद कमजोर पड़ी एआईएडीएमके एक बार फिर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि इस बार यहां अभिनेता विजय की एंट्री से चुनावी परिदृश्य बदल सकता है। हाल ही में उन्होंने अग्निनय से किनारा करके पूरी तरह से खुद को राजनीति में झोंक दिया है। बीती कई जनसभाओं में उमड़ी भारी भीड़ भी इस पर मुहर लगा रही है कि विजय ने खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया है। वहीं, बात अगर भाजपा की करें तो द्रमुक सरकार के सामने भाजपा अब तक कोई मजबूत सहयोगी खड़ा नहीं कर पाई है। द्रविड़ राजनीति और क्षेत्रीय अस्मिता के कारण भाजपा की राह यहां सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण भारत में भाजपा

की सफलता बिना स्थानीय सहयोगियों और क्षेत्रीय मुद्दों के संभव नहीं है।

केरल में भी राह आसान नहीं

केरल में भी इसी साल विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। यहां की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। वर्तमान में यहां एलडीएफ की गठबंधन सरकार है। 2021 में यहां एलडीएफ ने दोबारा सरकार बनाई थी, उसे तब 99 सीटें मिली थी। वहींस यूडीएफ के हिस्से में 41 सीटें आई थी। भाजपा की बात करें तो भगवा पार्टी ने यहां 2021 और उससे पहले 2016 में बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ा जरूर लेकिन वह खाता खोलने में नाकाम रही। हालांकि 2025 में भाजपा ने केरल में बिना किसी विधायक के अपनी सियासी आक्रामकता दिखाते हुए निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र के तिरुवनंतपुरम के नगरपालिका चुनाव में अपने प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। हालांकि नगर निकाय चुनावों में सीमित सफलता के बावजूद भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव अब भी बड़ी चुनौती हैं। वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन की जड़ें राज्य में गहरी हैं।

असम

20 मई 2026 को असम की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिस कारण 126 सीटों वाले इस राज्य में साल की शुरुआत से पहले ही चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 75 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की थी। इनमें से 60 सीटें अकेले भाजपा ने जीती थीं, जिससे पार्टी की मजबूत स्थिति सामने आई थी। हालांकि 2026 का चुनाव मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के लिए सत्ता को बरकरार रखने की बड़ी परीक्षा साबित होने जा रहा है। पिछले लगभग एक दशक से राज्य में भाजपा नीत सरकार होने के कारण सत्ता विरोधी लहर एक अहम चुनौती बन सकती है। इसके बावजूद सरमा ने पूरी आक्रामकता के साथ दावा किया है कि इस बार एनडीए 126 में से 104 सीटें जीत सकता है। उनका यह भरोसा न सिर्फ रणनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भाजपा चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी में है।



पुडुचेरी

पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनाव मार्च से मई के बीच कराए जाने की संभावना है। 30 सदस्यीय विधानसभा वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। फिलहाल यहां मुख्यमंत्री एन. रंगसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) और भाजपा का गठबंधन सत्ता में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी ने 10 और भाजपा ने 6 सीटें जीतकर मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार एआईएनआरसी और भाजपा गठबंधन के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती सरकार को एकजुट बनाए रखने की है। गठबंधन भीतरी खींचतान और सत्ता विरोधी माहौल के कारण दबाव में है। हाल ही में पुडुचेरी के इकलौते दलित मंत्री एके साई जे सरवनन कुमार के इस्तीफे ने इन अंतर्विरोधों को खुलकर सामने ला दिया। इस घटनाक्रम से न सिर्फ स्थानीय भाजपा इकाई में असंतोष उजागर हुआ, बल्कि पूरे गठबंधन में दरारें भी स्पष्ट हो गईं।

संगठन में बदलाव का होगा असर?

2025 के अंत में बिहार के विधायक नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। इसे भविष्य में नेतृत्व हस्तांतरण की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां जे.पी. नड्डा के बाद नया चेहरा सामने आ सकता है। वहीं, 2025 ने यह साफ कर दिया कि भाजपा आज भी देश की सबसे संगठित और चुनावी तौर पर सक्षम पार्टी है। लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में उसे न सिर्फ सत्ता विरोधी माहौल, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता और मजबूत स्थानीय

नेतृत्व से भी जूझना होगा।

आर्थिक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से विकास की नई दिशा चुनी

2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। साल 2025 को भारत के समकालीन इतिहास में केवल एक आर्थिक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक और नीतिगत बदलाव के वर्ष के तौर पर देखा जाएगा। यह वह साल रहा जब भारत ने यह फैसला किया कि अब सुधारों को लेकर हिचकिचाहट नहीं होगी, न कानूनों में, न टैक्स में और न ही शासन की सोच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार अब सिस्टम बदलने वाले फैसले लेगी और पुराने ढांचों को ढोने के बजाय उन्हें तोड़कर नया बनाने के लिए तैयार है। यह बदलाव केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने यह संकेत भी दिया कि भारत अपनी विकास यात्रा को अब छोटे कदमों से नहीं, बल्कि बड़े निर्णयों से आगे बढ़ाना चाहता है। 8.2 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ अपने आप में एक मजबूत आंकड़ा है, लेकिन इसका असली महत्व इस बात में छिपा है कि यह वृद्धि ऐसे समय में आई, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, युद्ध, आपूर्ति बाधाओं और महंगाई के दबाव से जूझ रही थी। यह बढ़त किसी एक सेक्टर की तेजी का नतीजा नहीं बल्कि उस व्यापक सुधार प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें टैक्स प्रणाली को सरल किया गया, श्रम कानूनों को स्पष्ट बनाया गया, निवेश के रास्ते खोले गए और व्यापार को नियमों के डर से बाहर निकालने की कोशिश की गई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2025 में

भारत की आर्थिक नीति ने स्टेबिलिटी से आगे बढ़कर स्केल की ओर कदम रखा।

श्रम सुधार: विकास की निर्णायक नींव

श्रम सुधार अक्सर राजनीतिक बहसों में सबसे ज्यादा विरोध झेलते हैं, लेकिन 2025 ने दिखाया कि अगर बदलाव को स्पष्टता और संतुलन के साथ लागू किया जाए, तो उसका असर सकारात्मक हो सकता है। 29 पुराने श्रम कानूनों को चार कोड्स में समेटना केवल प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि यह उस भ्रम को खत्म करने की कोशिश थी, जो दशकों से उद्योगों और कामगारों, दोनों को परेशान कर रहा था। इन सुधारों का महत्व इस बात में है कि इन्होंने कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किए बिना उद्योगों को स्पष्ट नियम दिए। महिला श्रम भागीदारी, संगठित रोजगार और औद्योगिक संबंधों में स्थिरता जैसी चीजों पर इसके दीर्घकालिक असर दिखेंगे। ऋजु को दो स्लैब में लाना और इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करना न केवल सरकार की आय पर असरकारी होने थे बल्कि इसने सरकार में लोगों का भरोसा मजबूत किया। ऋजु सुधारों ने यह संदेश दिया कि टैक्स प्रणाली का मकसद केवल वसूली करना नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बाजार में खपत बढ़ने, त्योहारों के दौरान रिकॉर्ड बिक्री से और टैक्स कलेक्शन के स्थिर रहने से इस सोच को और मजबूती मिली। इसका असर सीधे दिखा रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुईं, छोटे कारोबारियों का कंप्लायंस बोझ घटा और टैक्स विवाद और नोटिस कम हुए। दूसरी तरफ, इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 को हटाकर नया कानून लाना एक प्रतीकात्मक कदम बना जिसने औपनिवेशिक जटिलता से आधुनिक सरलता की ओर कदम बढ़ाना कहा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह टैक्स केवल राहत नहीं बल्कि यह संकेत भी था कि नीति निर्माता घरेलू बजट की वास्तविकताओं को भी समझते हुए फैसले ले रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि इस साल दिवाली में 6.05 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज हुई और नवरात्रि की खरीदारी एक दशक में सबसे मजबूत रही।

जन विश्वास सुधार: शासन की भाषा में बदलाव

2025 में जन विश्वास सुधार के तहत सर. कार ने 200 से ज्यादा छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया। स्क्व स्टॉक रजिस्टर में तकनीकी गलती, बीज कानून में लेबलिंग



की छोटी चूक, पर्यावरण नियमों में मामूली देरी, फ़ैक्ट्री रिटर्न भरने में साधारण त्रुटि, जैसे मामलों में जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना होगा। छद्म। शासित राज्यों ने भी मिलकर 1,000 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सोच का बदलाव था— सरकार अब डराने वाली नहीं, सहयोग करने वाली दिखी। छोटे-छोटे तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना केवल कानून में संशोधन नहीं है, यह शासन की मानसिकता में बदलाव है। जब सरकार यह मानती है कि हर गलती अपराध नहीं होती, तो वह नागरिक और उद्यमी— दोनों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाती है। यह बदलाव खासतौर पर डेडम और छोटे व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अब नोटिस और मुकदमों के डर के बिना काम कर सकते हैं। 2025 को इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस का रीसेट साल भी कहा गया। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा में 76 उत्पादों से अनिवार्यता हटाई गई, 200 से अधिक कैटेगरी डीरेगुलेट किए गए। पहले छोटे स्टील या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वालों को हर बैच पर महंगा सर्टिफिकेशन कराना पड़ता था। अब छोटे उत्पादों को इस बोझ से राहत मिलेगी। एमएसएमई की नई परिभाषा और इंड्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति यह दिखती है कि भारत अब नियंत्रण की जगह प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दे रहा है। इससे विदेशी पूंजी आएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके

साथ यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों के साथ हुए व्यापार समझौते इस बात का संकेत हैं कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है। 100 डॉलर बिलियन निवेश प्रतिबद्धता वाला म्ज। समझौता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक विश्वास का भी प्रमाण है।

न्यूक्लियर सुधार, ग्रामीण रोजगार और कानून: भविष्य की तैयारी

शांति बिल, ग्रामीण रोजगार गारंटी का विस्तार और भारतीय न्याय संहिता, ये तीनों सुधार यह दिखाते हैं कि सरकार ने 2025 को केवल आर्थिक सुधारों तक सीमित नहीं रखा। न्यूक्लियर सेक्टर को नियंत्रित लेकिन निवेश-अनुकूल बनाना, ग्रामीण रोजगार को राहत से जोड़कर संपत्ति निर्माण की ओर ले जाना और 160 साल पुराने प्ल को बदलना। भारतीय न्याय संहिता (ठहै) ने 160 साल पुराने प्ल को हटाया। अब भारत का कानून साइबर क्राइम को पहचानता है, म-थ्र की सुविधा देता है और समयबद्ध ट्रायल को अनिवार्य करता है। ये फैसले इस बात का संकेत हैं कि नीति निर्माता अल्पकालिक लाभ से आगे की सोच रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेय 2025 के तहत रोजगार गारंटी 100 दिनों की बजाए 125 दिनों की होगी। काम को गांव की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया साथ ही इसके डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी।

2025 ने भारत की दिशा तय की

2025 को लेकर मतभेद हो सकते हैं, आलोचनाएं भी होंगी जैसा कि किसी भी बड़े बदलाव के साथ होता है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यह साल भारत के सुधार विमर्श में एक स्पष्ट मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। 2025 वह साल रहा जब भारत ने तय कर लिया कि वह सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ेगा। यह वह साल रहा जब भारत ने तय किया कि विकास केवल नारे से नहीं, बल्कि कठिन फैसलों, सरल कानूनों और भरोसे पर आधारित शासन से आता है। ये सुधार की ठोस नींव हैं— जहां कानून सरल हों, टैक्स न्यायपूर्ण हो, कारोबार आसान हो और अवसर हर नागरिक तक पहुंचे। अगर आने वाले वर्षों में इन सुधारों की निरंतरता बनी रही, तो 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की आगे की राह क्या होगी?

भारत की राजनीति के लिहाज से साल 2025 भी कई मायनों में अहम रहा, जिसने एक बार फिर देश को प्रभावित किया है। साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान भगदड़ की घटना हुई। इसमें मारे गए लोगों की संख्या को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सैन्य संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बना। वहीं, अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रिश्तों



तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दी। इसी साल बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हुई। कांग्रेस ने इसे लेकर श्वोट चोरीश का आरोप लगाते हुए अभियान चलाया, और बाद में चुनाव आयोग ने देश के बड़े हिस्से में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब नजर अगले साल होने वाले चुनावों पर है। असम, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं आने वाले साल में किस तरह के रंग दिखाती हैं। साथ ही यह सवाल भी अहम है कि 2024 के आम चुनावों में झटके के बाद एनडीए ने इस साल कैसे वापसी की। इंडिया गठबंधन के नाम से बने विपक्षी मोर्चे का भविष्य क्या है, कांग्रेस की रणनीति और पार्टी के नेतृत्व को लेकर क्या संकेत मिलते हैं। इसके अलावा, क्या भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' या अमेरिका के टैरिफ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई असर पड़ा, और विभिन्न नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर क्या संदेश देना चाहती है।

इंडिया गठबंधन का भविष्य

इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। द ट्रिब्यून की एसोसिएट एडिटर और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति टंडन का कहना है कि अगले साल राजनीति से जुड़ी सबसे अहम खबरों में से एक यह होगी कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या रहेगा। अदिति टंडन के मुताबिक, अगर असम और पुद्दुचेरी को अलग कर दें, जहां

एनडीए की सरकार है और असम में भाजपा सत्ता में है, तो बाकी राज्यों में ज्यादातर अहम सरकारें इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों की हैं। सवाल यह है कि ये सरकारें अपने मौजूदा राजनीतिक आधार को कितनी मजबूती से बचा पाती हैं और उसे कितना आगे बढ़ा पाती हैं। इसी पर तय होगा कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। उनका कहना है कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति भी इस पूरे समीकरण में अहम भूमिका निभाती है। वह कहती हैं कि कांग्रेस के लिए हालात बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहे हैं। पार्टी अपनी आंतरिक चुनौतियों और अंतर्विरोधों की वजह से लगातार सिमटती नजर आ रही है। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन वह कैसे बनेगा, यह जिम्मेदारी विपक्ष की ही है। यह न तो जनता पर निर्भर करता है और न ही भाजपा पर। कांग्रेस नेतृत्व को ही तय करना होगा कि पार्टी और इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। यही तय करेगा कि भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं राजनीति

तिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि हाल में हुए चुनावों के नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए उत्साहजनक नहीं रहे हैं। उनके मुताबिक, चुनावी आंकड़े साफ बताते हैं कि 2025 का साल चुनावी नजरिए से इंडिया गठबंधन के लिए अनुकूल नहीं रहा। गठबंधन को एक के बाद एक चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। संजय कुमार कहते हैं कि कुछ राज्यों में उम्मीदें जरूर थीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे राज्य में माना जा रहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। कुल मिलाकर, चुनावी लिहाज से 2025 का साल इंडिया गठबंधन के लिए काफी मुश्किल भरा रहा और इसे बड़ा झटका लगा।

बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते

बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों पर अदिति टंडन का कहना है कि हालात सामान्य हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में कहा कि परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। इस बयान के जरिए उन्होंने बीजेपी और संघ के बीच मतभेद की चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हालांकि उसी सम्मेलन में मोहन भागवत ने बीजेपी को यह भी याद दिलाया कि अब वक्त आ गया है और पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए। अदिति टंडन के मुताबिक, अपने तरीके से उन्होंने यह संदेश दे दिया कि अब थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि काफी समय बीत चुका है। लोग यह महसूस करने लगे थे कि जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, तो संगठनात्मक अनुशासन कमजोर पड़ता है। उनका कहना है कि संघ भले ही



सार्वजनिक तौर पर यह कहता हो कि वह इन मामलों में सीधे दखल नहीं देता, लेकिन कन संघ की कार्यशैली को समझना आसान नहीं है। यह एक जटिल संगठन है। अदिति टंडन की समझ के मुताबिक, संघ बीजेपी को नाम सुझाने के बजाय एक व्यापक ढांचा देता है। यानी यह बताया जाता है कि किस तरह की पात्रता वाला व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त होगा, ताकि उसके साथ काम करने में संघ को भी सहजता रहे। उनके मुताबिक, नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद यह तस्वीर और साफ हो गई। संघ की ओर से बीजेपी को चार अहम बातें बताई गई थीं, जिनका जिक्र उन्होंने अपने कॉलम में भी किया है। पहली शर्त यह थी कि उम्मीदवार की उम्र 50 साल से कम हो। दूसरी, वह दिल्ली सर्कल से जुड़ा पारंपरिक नेता न हो। तीसरी, उसे संसदीय लोकतंत्र और संगठनात्मक ढांचे दोनों का पर्याप्त अनुभव हो। और चौथी शर्त यह थी कि नियुक्ति करते समय जातिगत संतुलन से ऊपर उठकर, यानी कास्ट न्यूट्रैलिटी को ध्यान में रखा जाए। अदिति टंडन कहती हैं, राज्यों और अन्य संगठनात्मक पदों पर क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन जरूरी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को जाति-निरपेक्ष बनाए रखने पर जोर दिया गया। इसी संदर्भ में नितिन नवीन का नाम सामने आता है। वह कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसकी बिहार में आबादी एक प्रतिशत से भी कम है। इस तरह वह कास्ट न्यूट्रैलिटी समेत संघ द्वारा तय किए गए सभी मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। बीजेपी की रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि पार्टी ने हाल के वर्षों में नेतृत्व को लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया है। उनके मुताबिक, अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,



राजस्थान, दिल्ली और ओडिशा को देखें, तो इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तौर पर आपको ज्यादातर युवा चेहरे नजर आते हैं। ये सभी अपने-अपने राज्यों में पार्टी के उभरते हुए युवा नेता हैं। संजय कुमार कहते हैं कि इससे बीजेपी का संदेश साफ तौर पर सामने आता है। उनका कहना है कि पार्टी यह दिखाना चाहती है कि अब युवाओं को आगे लाने की जरूरत है। इसका मतलब सिर्फ चुनाव लड़वाना नहीं है, बल्कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियाँ देना भी है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है।

अगले साल होने वाले चुनाव

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की भूमिका अहम रहने वाली है।

उनके मुताबिक, अगर इन राज्यों पर नजर डालें तो असम में बीजेपी की सरकार है। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी जोर लगाया था और तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की दावेदारी काफी मजबूत रहने वाली है। संजय कुमार कहते हैं कि दक्षिण भारत की स्थिति थोड़ी अलग है उनका कहना है, तमिलनाडु में बीजेपी का अब तक कोई बड़ा संगठनात्मक विस्तार नहीं है। वहां पार्टी के लिए चुनौती रहेगी। यह ऐसा राज्य है जहां चुनाव मुख्य तौर पर क्षेत्रीय दलों के बीच होता है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किस तरह के गठबंधन करती है, ताकि किसी पार्टी के साथ मिलकर या तो चुनाव जीत सके या कम से कम मजबूत चुनौती दे सके। केरल को लेकर संजय कुमार का कहना है कि वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य पारंपरिक तौर पर अलग रहा है। उन्होंने कहा कि केरल में आमतौर पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता का बदलाव होता रहा है। लेकिन हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने कुछ नए संकेत दिए हैं। खासकर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। ऐसे में केरल के विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर रहेगी। बीजेपी वहाँ कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं अदिति टंडन का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से बीजेपी ने तेजी से सबक लिया। उनके मुताबिक, उस दौर में आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को लेकर भी चर्चाएं सामने आई थीं और इनमें से कई बातें सही भी थीं। लेकिन बाद में दोनों एक साथ आए और उसका असर दिल्ली और बिहार

“

बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि अब युवाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब सिर्फ चुनाव लड़वाना नहीं है, बल्कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियाँ देना भी है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है।

संजय कुमार

निदेशक, सीएसडीएस



“

राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने वाला कोई विपक्षी नेता माना जाता है, तो कई राजनीतिक विश्लेषक ममता बनर्जी का नाम लेते हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही यह जानते हैं कि यह मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है।

अदिति टंडन

असोसिएट एडिटर और दिल्ली ब्यूरो चीफ़, द ट्रिब्यून



से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल को लेकर अदिति टंडन कहती हैं कि बीजेपी इसे अपने लिए सबसे बड़ा मौका मानती है। बीजेपी को लगता है कि पश्चिम बंगाल उनके लिए सबसे बेहतर अवसर है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने वाला कोई विपक्षी नेता माना जाता है, तो कई राजनीतिक विश्लेषक ममता बनर्जी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही यह जानते हैं कि यह मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। बीजेपी के पास यहाँ खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए दांव कहीं ज्यादा बड़े हैं।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद क्या पीएम मोदी की छवि पर असर पड़ा?

भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर असर को लेकर उठे सवाल पर द ट्रिब्यून की एसोसिएट एडिटर अदिति टंडन का कहना है कि इस घटना का प्रधानमंत्री की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उनके मुताबिक, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की छवि पर इसका बिल्कुल भी असर हुआ। अगर ऐसा होता, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए चुनावों में उसका असर साफ दिखाई देता। लेकिन हमने देखा कि उन चुनावों में किस तरह बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को जीत मिली। अदिति टंडन का कहना है कि उस समय कूटनीतिक विशेषज्ञों से बातचीत में भी यही राय सामने आ रही थी। डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट्स का मानना था कि संयम बरतने का वक्त है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्तर पर जाकर सीधे इस तरह शामिल होने

की जरूरत नहीं है। यह दो स्वतंत्र देशों का मामला है, जो अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव किसी भी नेता की छवि का एक अहम पैमाना होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई होती, तो उसका असर चुनावी नतीजों में जरूर दिखता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा नहीं हुआ। इससे यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की छवि पर इस घटना का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। अदिति टंडन के मुताबिक, कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का संकेत दिया है। वह कहती हैं, प्रधानमंत्री ने अब तक जिस तरह अमेरिका के दबावों के बावजूद, टैरिफ जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति बनाए रखी है, उससे यह पहली बार साफ तौर पर महसूस हुआ कि भारत एक मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के साथ अपने संबंध भी संतुलित तरीके से बनाए रखने में सफल रहा है।

कांग्रेस का नेतृत्व

कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों पर अदिति टंडन का कहना है कि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी उलझी हुई नेतृत्व संरचना है। उनके मुताबिक, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज उसकी कंप्यूज्ड लीडरशिप है। बिहार में एसआईआर को चुन। एवी मुद्दा बनाने का फैसला राहुल गांधी का ही था। अदिति टंडन कहती हैं कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी की भूमिका भी लगातार सवालों के घेरे में रही। उन्होंने कहा कि सत्र के शुरुआती दिनों में राहुल गांधी संसद में आए और प्रदूषण का मुद्दा उठाया। लेकिन उसके बाद वह नजर नहीं आए और जर्मनी चले गए। ऐसा नहीं है कि राहुल

गांधी लोगों से अपील नहीं करते, लेकिन उनकी राजनीति अस्थिर दिखाई देती है। अदिति टंडन का मानना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का सार्वजनिक संवाद राहुल गांधी से अलग नजर आता है। उन्होंने कहा कि जब प्रियंका गांधी बोलती हैं, तो उनकी बातें ज्यादा तार्किक और भरोसेमंद लगती हैं। वह शांत नजर आती हैं और अपनी बात कहने का उनका तरीका अलग है। इसके उलट राहुल गांधी अक्सर गुस्से में दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करते हुए नजर आते हैं। अदिति टंडन के मुताबिक, प्रियंका गांधी के भाषणों की इसी वजह से काफी सराहना भी हुई है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है कि सरकार और विपक्ष के बीच संवाद ही न हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी और सरकार के बीच वह संवाद नहीं है, जितना होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सरकार भी संवाद के रास्ते तलाशे और कांग्रेस भी ऐसा पुल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों ही लोकतंत्र के अहम स्तंभ हैं। वहीं रा. जनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि एसआईआर को चुनावी मुद्दा बनाना आसान नहीं है। उनके मुताबिक, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। संजय कुमार कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से कट जाता है, तो वह तकनीकी तौर पर मतदाता ही नहीं रहता। उन्होंने कहा, ऐसे में उसके लिए चुनाव में भागीदारी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरी तरफ, जिन लोगों के वोट बने रहते हैं, उनके सामने अगर पार्टियां यह कहती हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, तो उन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका वोट सुरक्षित होता है। उनका कहना है कि जिन लोगों के वोट कट चुके होते हैं, वे मतदान कर ही नहीं पाते, इसलिए यह मुद्दा चुनावी रूप से असरदार नहीं बन पाता। यही वजह है कि यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा नहीं बन सका। यह ज्यादातर पार्टियों तक ही सीमित रहा। संजय कुमार का मानना है कि विपक्ष को जमीनी और रोजमर्रा के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ें, तो ये मुद्दे कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। विपक्ष को सरकार की कमियों को लेकर लोगों के पास जाना होगा और उन्हें साफ-साफ समझाना होगा।

अकूत तेल की अतृप्त ललक में डोनाल्ड ट्रंप



प्रभात कुमार सिंह
पूर्व नीकरशाह
और विदेश मामलों के
विशेषज्ञ

विश्व पटल पर यक्ष प्रश्न उभर कर आया है कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण अंजाम देने और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करने के पीछे वास्तविक मकसद क्या है? क्या वास्तव में ड्रग तस्करों के सरगना होने के संगीन इल्जाम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अमेरिका द्वारा अपहरण किया गया है? अथवा इसके पीछे क्या अन्य विशिष्ट कारण विद्यमान रहे हैं? तकरीबन साढ़े तीन करोड़ आबादी वाले वेनेजुएला दुनिया में भारी तेल के अकूत भंडार मौजूद हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है की तकरीबन 303 बिलियन बैरल तेल का विराट भंडार वेनेजुएला की जमीन के अंदर अभी विद्यमान है। अकूत तेल संपदा के अतिरिक्त रेयर मिनरल्स का भी विराट भंडार वेनेजुएला में विद्यमान है, जिसमें कॉपर, चांदी, सोना, आदि शामिल हैं। वेनेजुएला का तेल वस्तुतः भारी किस्म का तेल माना जाता है। अमेरिका की सरजमीं में जो तेल विद्यमान है, वह तो बहुत हल्के किस्म का तेल है। अमेरिका में तेल की विशाल मात्रा मौजूद है और अमेरिका तेल का एक निर्यातक देश भी है। इसके स्थिति के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय कानून का घनघोर उल्लंघन करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आक्रामक तौर पर अपहरण अंजाम दिया गया। वेनेजुएला में तेल की खोज सन 1922 में प्रारंभ हुई थी। वेनेजुएला में अमेरिकन तेल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया और वेनेजुएला के तेल भंडारों से तेल का बड़ी मात्रा में दोहन भी किया। एक ऐतिहासिक दौर में दुनिया की तकरीबन सौ से अधिक तेल कंपनियां वेनेजुएला से तेल को



निकाल रही थी। सन् 1976 को कार्लोस आंद्रेस पेरेज नामक एक राष्ट्रपति वेनेजुएला में सत्तानशीन हुआ, जिसके द्वारा तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी अनेक अमेरिकन तेल कंपनियां वेनेजुएला में तेल का दोहन निरंतर करती रहीं। 1999 ह्यूगो शावेज नामक एक साम्यवादी फितरत का राष्ट्रपति वेनेजुएला की राजसत्ता पर आसीन हुआ और उसके द्वारा अमेरिकन तेल कंपनियों को वेनेजुएला से निकाल बाहर किया गया। राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की अत्यधिक निकटता साम्यवादी क्यूबा और चीन जैसे वामपंथी मुल्कों के साथ अत्यंत घनिष्टता के साथ स्थापित हो गई। सन् 2013 में ह्यूगो शावेज की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के तौर पर निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा भी ह्यूगो शावेज की कठोर वामपंथी नीतियों का बाकायदा अनुसरण जारी रखा गया। साम्यवादी क्यूबा की तरह वेनेजुएला भी अमेरिका की आंखों का विकट कांटा बन गया और साम्यवादी क्यूबा की तरह से ही वेनेजुएला पर भी अमेरिकन हुकूमत द्वारा कड़े आर्थिक प्रतिबंध आयद कर दिए गए। अमेरिका



द्वारा आयद किए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ही भारत की ओएनजीसी कंपनी को अपना कारोबार वेनेजुएला से समेटना पड़ गया। ओएनजीसी को करोड़ों धनराशि वेनेजुएला में फंसी हुई है।

उल्लेखनीय है कि सन् 1959 में लैटिन अमेरिकन देश क्यूबा में फिदेल कास्त्रो और चे गुएवरा की कयादत में साम्यवादी इंकलाब हुआ। साम्यवादी क्यूबा से प्रेरित होकर अनेक लैटिन अमेरिकन देशों में जिनमें वेनेजुएला भी शामिल था वामपंथी हुकूमतों की स्थापना हुई। लैटिन अमेरिका में वामपंथी देशों का प्रभाव शनः शनः बढ़ने लगा। आधुनिक इतिहास में अमेरिका द्वारा 41 दफा लैटिन अमेरिकन देशों में सशस्त्र दखलंदाजी से सत्ता परिवर्तन अंजाम दिया जा चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में आक्रमण अंजाम देते हुए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करने के पश्चात आयोजित कांफ्रेंस में फिर से एक बार मुनरो डॉक्ट्रिन का उल्लेख किया गया है। सन् 1823 के बाद जब से मुनरो डॉक्ट्रिन का ऐलान किया गया था, तभी से अमेरिका व्यावहारिक तौर पर समस्त लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव क्षेत्र वाला गलियारा मानता है।

...तो ऐसे बर्बाद हुआ वेनेजुएला



सन् 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन के ऐलान के वक्त दुनिया में यूरोपीयन साम्राज्यवाद का बोलबाला था। लैटिन अमेरिकन देशों को यूरोपीयन साम्राज्यवाद से बचाने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मुनरो ने इस डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था। अमेरिका स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सैन्य युद्ध करके सन् 1776 में आजाद हुआ। आज के दौर में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में सैन्य दखल दोते हुए साम्राज्यवाद विरोधी मुनरो डॉक्ट्रिन का हवाला दिया जाना, वस्तुतः नव-साम्राज्यवादी व्यवहार करते हुए एक विद्रुपता के अलावा कुछ भी नहीं है। वेनेजुएला पर आक्रमण के पीछे वस्तुतः एक टायकून बिजनेसमैन की पृष्ठभूमि से दूसरी दफा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए डोनाल्ड ट्रंप का वास्तविक मकसद वेनेजुएला के अकूत तेल भंडार को सैन्य शक्ति के बल पर हथियाना है। राष्ट्रपति ट्रंप की सोच समझ में दूरदर्शी राजनीति निहित नहीं है ना ही कुशल कूटनीति निहित है, डोनाल्ड ट्रंप की नीति और नियत में अमेरिका के लिए केवल दौलत का लोभ लालच निहित रहता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुलंद किए गए अमेरिका ग्रेट अगेन निर्मित करने के मकसद के पीछे केवल अमेरिका को और अधिक दौलतमंद बनाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पराभाव हो जाने के पश्चात विश्व

पटल एक तरफ पूर्वी यूरोप में साम्यवादी देशों का उदय हुआ और दूसरी तरफ नव-साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका का उदय हुआ। 1949 में चीन में साम्यवादी सत्ता का उदय हुआ। एशिया में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के खातिर अमेरिका ने वियतनाम में सैन्य दखल अंदाजी अंजाम दी, जिसका परिणाम अमेरिका की घनघोर पराजय में हुआ।

उल्लेखनीय है कि सन् 2019 में वर्ल्ड बैंक ट्रिब्यूनल ने एक आदेश को पारित किया था, जिसके तहत वेनेजुएला हुकूमत के लिए हुक्म जारी किया गया था कि वह अमेरिकन तेल कंपनियों को समुचित मुआवजा प्रदान करें, जिनकी विराट पूंजी और संपदा को वेनेजुएला सरकार द्वारा तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण द्वारा जप्त कर लिया गया था और बिना कोई मुआवजा दिए वेनेजुएला से निष्कासित कर दिया गया था। वर्ल्ड बैंक की इसी आदेश का हवाला देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के समस्त तेल को अमेरिका का तेल घोषित कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप दावा पेश कर रहे हैं कि अब वेनेजुएला को अमेरिका संचालित करेगा। वेनेजुएला के तेल पर आधिपत्य स्थापित करने की पृष्ठभूमि में डोनाल्ड ट्रंप का एक रणनीतिक मकसद भी निहित है। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के तेल पर आधिपत्य स्थापित करने के साथ

ही रूस और चीन जैसे देशों को भी वेनेजुएला से बाहर कर देना चाहते हैं, जिनकी तेल कंपनियों द्वारा बहुत बड़ा निवेश वेनेजुएला में किया गया है। चीन द्वारा वेनेजुएला में उत्पादित 90 प्रतिशत तेल को खरीदा जाता है। शेष 10 प्रतिशत तेल उत्पादन का अधिकतर भाग रूस द्वारा खरीद लिया जाता है। इस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा आयद किए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई भी वास्तविक प्रभाव वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर कायम नहीं हो सका। इन वास्तविक हालात से शुब्ध होकर बौखलाए हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना घोषित करते हुए उनकी पत्नी सहित अगवा कर लिया गया।

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के पश्चात वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वेनेजुएला की संसद में डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि हम ऊर्जा क्षेत्र की महाशक्ति हैं। इसी कारण से हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना है। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका का ऊर्जा लालच हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला की हुकूमत पर मादक पदार्थ तस्करी और लोकतंत्र मानव अधिकार से जुड़े हुए सभी झूठे दावों का उन्होंने खंडन किया। वेनेजुएला ऐसे तमाम ऊर्जा संबंधों के लिए खुला है जहां सभी पक्षों को फायदा हो और यही ही हमारे ऊर्जा संबंधों की विविधता भी है। डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक लोभ लालच आखिरकार अमेरिका के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्ताव पेद्रो को भी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी तो फिर गुस्ताव पेद्रो ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति को जान लेना चाहिए कि लैटिन अमेरिका साम्राज्यवाद के विरुद्ध बहुत लंबी लड़ाई लड़कर आजाद हुआ है। लैटिन अमेरिकन देश अमेरिकन नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी छापामार युद्ध के लिए मजबूर हो जाएंगे।

उत्तर भारत की प्राचीन 'ग्रीन वॉल' पर क्यों छिड़ा है संग्राम



संजय सिन्हा
हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

गुरुग्राम से कुछ ही दूर क्वार्टाइट की पुरानी लकीरें उभर आती हैं। कोई हिम रेखा नहीं, कोई पोस्टकार्ड-शिखर नहीं, बस घिसी-छिली-कुतरी और ध्वस्त पहाड़ियाँ, जैसे पृथ्वी ने अपनी सबसे पुरानी हस्तलिपि पत्थर पर ही लिख छोड़ी हो। अरावली में ऐसे 'पोस्टकार्ड-शिखर' कम हैं, यानी यह उतनी नाटकीय ऊँचाई वाली नहीं दिखती, लेकिन उसका पर्यावरणीय काम बहुत बड़ा है। धूल को रोकना, पानी रीचार्ज करना, जैव विविधता की रक्षा करना और अपनी गोद में वन्यजीवों का लालन-पालन। यही अरावली है। उत्तर-पश्चिम भारत की वह पर्वतमाला, जिसे वैज्ञानिक साहित्य और लोकप्रिय भू-ज्ञान दोनों श्मशान की सबसे पुरानी फोल्ड-माउंटन बेल्ट के रूप में पहचानते हैं। लोकइतिहासकार श्रीकृष्ण जुगनू बताते हैं, यह वह पर्वत शृंखला है, जिसमें लूनी, बनास, साबरमती,

साहिबी, बेड़च (आयड़), खारी, सूकड़ी, कोठारी, सोम, जाखमी, कमला नदियाँ और नक्की, पुष्कर, जयसमंद, मातृकुंडिया, बेणेश्वर जैसी झीलें हैं।

भारत की रीढ़

अरावली भारत की रीढ़ है, जो चार राज्यों से गुजरती है। यह उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग 670 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। यह दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के भीतर गहराई तक जाती है, और फिर गुजरात में अहमदाबाद के आसपास के मैदानों तक पहुंचती है। इसका सबसे ऊँचा शिखर गुरु शिखर है, जो लगभग 1,722 मीटर है और यह राजस्थान के माउंट आबू में है। यहां आप खड़े होंगे तो बादल आपको छूकर निकलेंगे। भूगोलविद सीमा जालान बताती हैं कि अरावली 67 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है और यह नहीं होती तो उत्तर भारत की जाने कितनी नदियाँ नहीं होतीं। जाने कितने जंगल, कितनी वनस्पतियाँ, कितने बहुमूल्य धातु

और कितने इकोलॉजिकल वैभव नहीं होते। अरावली संस्कृत के 'अर्बुदावलि' से बना है। इसे राजस्थान के इतिहास में 'आडावळ' के नाम से पुकारा जाता है। यह पर्वतराजा एक तरह की रक्षा-पंक्ति भी है, जो रेगिस्तान, धूल और जल-अभाव के खिलाफ चुपचाप खड़ी रही है। यह उत्तर भारत का सबसे पुराना 'टाइम कैप्सूल' और सबसे नाजुक वर्तमान है। अरावली की प्राचीनता अक्सर एक रा. 'मांचक तथ्य' की तरह दोहराई जाती है शहिमालय से भी पुरानी। लेकिन यह तुलना सिर्फ उम्र दिखाती है खतरा नहीं। भूगोलविदों का कहना है कि हिमालय युवा है, बढ़ रहा है अरावली बूढ़ी है। भूविज्ञान की भाषा में यह प्रोटेरोजोइक और उससे जुड़े युगों के लंबे घटनाक्रम से बनी, जब भारतीय प्लेट और प्राचीन क्रस्ट-खंडों ने टकराव, रिफ्टिंग, अवसादन और रूपांतरण के चक्र झेले। इस प्रक्रिया को कई स्रोत 'अरावली-डेल्टा ऑर्गेनिक बेल्ट' के रूप में रेखांकित करते हैं। एक ऐसा भू-खंड,



जो महाद्वीपीय टुकड़ों की टक्कर और धीरे-धीरे हुए पर्वत-निर्माण के परिणामस्वरूप उभरा। यह बताता है कि अरावली की चट्टानें और उनके भीतर की दरारें एक ऐसे भू-तंत्र का हिस्सा हैं, जिसे बनना जितना कठिन था, टूटना उतना ही आसान हो सकता है क्योंकि टूटने के लिए विस्फोट नहीं चाहिए—बस लगातार खनन, कटिंग, सड़कें, और कंक्रीट।

उत्तर भारत की ग्रीन वॉल

अरावली को उत्तर भारत की 'ग्रीन वॉल' कहा जाता है। थार मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार। वनस्पति, मिट्टी, ढलानों और जल-धारण क्षमता का सम्मिलित तंत्र है। नागरिक समूहों और कुछ तकनीकी आकलनों में अरावली के भीतर कई शगैस-ब्रीच का उल्लेख मिलता है। ऐसे हिस्से जहां पहाड़ियों की निरंतरता टूट गई है, और धूल-रेत के लिए रास्ता खुला है। इस फ्रेम में दिल्ली-एनसीआर की धूल-आंधियाँ केवल मौसमी घटना नहीं, भूगोल का संकेत बन जाती हैं इस पर्वतमाला में छेद बढ़ रहे हैं। यह एक कठिन कहानी है, क्योंकि यहां कारण 'एक' नहीं हैं। कहीं अवैध खनन है, कहीं वैध खनन का विस्तार, कहीं अनियोजित शहरीकरण, कहीं सड़क-रेल जैसी रैखिक परिया-जनाएं, जो परिदृश्य को काटकर शटुक-

डॉर में बदल देती हैं। दिल्ली के भीतर शरिज, जिसे अरावली की उत्तरी कड़ी के रूप में देखा जाता है, शहरी पारिस्थितिकी का वह हिस्सा है, जिसे लोग पार्क की तरह देखते हैं, लेकिन वह मूलतः एक भू-रक्षात्मक संरचना है। यह धूल रोकने, सूक्ष्म जलवायु बनाने और जैव विविधता को टिकाए रखने वाला सुरक्षा तंत्र है। अरावली दूर से श्वंजर लगती है लेकिन यही वन्यजीवों का भी घर है। तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सियार, नीलगाय, साही और अनेक पक्षी प्रजातियां इसमें निवास करती हैं। हरियाणा-दिल्ली-राजस्थान के किनारों पर तेंदुए की उपस्थिति की खबरें बार-बार आती रही हैं, और वन्यजीव कॉरिडोर की चर्चा भी। इस कॉरिडोर का सवाल केवल श्रानवर बचाओ नहीं है यह परिदृश्य की अखंडता का सवाल है। जब पहाड़ों के बीच सड़कें और रियल-एस्टेट शकट-लाइन बनाते हैं तो आवास छोटे द्वीपों में बंट जाता है। छोटे द्वीपों में बड़े शिकारी टिकते नहीं और फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है और अंततः श्वन्यजीव तो रहे नहीं का बहाना बना कर विकास के बहाने विनाश आ बैठता है। अरावली के दक्षिणी हिस्से उदयपुर-मेवाड़ क्षेत्र में वन्यजीव का इतिहास सिर्फ प्राकृतिक इतिहास नहीं, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास भी है।

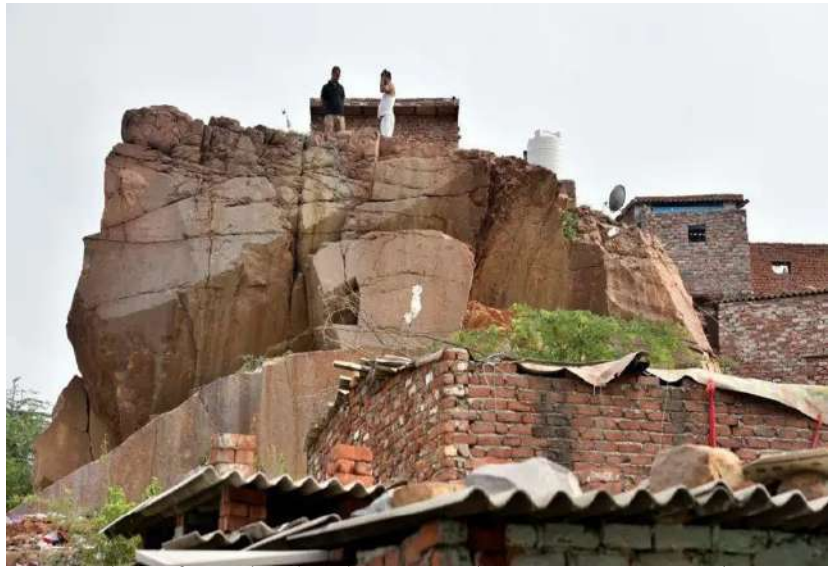
इतिहास का फॉरेंसिक सबूत

इसी संदर्भ में एमके रंजीत सिंह का उल्लेख खास महत्व रखता है। वह मेवाड़ में बाघों के पतन का एक कठोर लेखा प्रस्तुत करते हैं, जहां शिकार, वन-क्षरण और जंगली शाकाहारियों की कमी ने मिलकर पारिस्थितिकी की रीढ़ तोड़ दी। रंजीत सिंह लिखते हैं कि एक शासक ने शलगभग 200 वयस्क बाघ बनाए रखने की बात करते हुए भी अपने शासनकाल में 375 से अधिक बाघों का शिकार किया। इस पर इकोलॉजिकल हिस्टोरियन डॉक्टर भानु कपिल के निर्देशन में हाल ही डॉक्टर उमा भाटी ने अनुसंधान किया है। डॉक्टर भानु कपिल का कहना है कि अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो महाराणा प्रताप छोटी सेना के सहारे उस समय के मुगल बादशाह अकबर की विशालकाय सेना से मुकाबला कैसे कर सकते थे। उनका कहना है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए 32 किले बनवाए थे, जिन्हें ग्रीन फोर्ट के रूप में ऐतिहासिक माना जाता है। आज दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक उदयपुर अरावली के बिना नहीं बस सकता था। यह उस समय की रिंग फेंस सिटी थी, जो हर प्रकार के आक्रमणों से लोगों की सुरक्षा करती थी। अरावली ही वह प्राण तत्व है, जिसने जल, जंगल और जमीन का दर्शन दिया। डॉक्टर भानु कपिल का कहना है कि बिजौलिया का किसान आंदोलन हो या भील आंदोलन, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के सवाल से भी जुड़े थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश अधिकारियों ने जंगलों से वन्यजीवों के शिकार बढ़ा दिए थे। इस इलाके में केवड़े की नाल हो या चंदन के वृक्षों की कतारें या अन्य वनस्पतियां, अरावली के कारण ही रही हैं। कभी यहां चंदन और सागवान के वृक्ष इफरात में थे। वह आगे बताते हैं 1949-1954 के पांच वर्षों में मेवाड़ ने अरावली के लगभग 140 बाघ गंवाए यानी औसतन 28 बाघ प्रति वर्ष। यानी निष्कर्ष यह कि 1960 के दशक तक मेवाड़ में बाघ विलुप्त हो गया, साथ ही जंगल और जंगली शाकाहारी प्रजातियां भी लगभग खत्म हो गईं। इस तरह के तथ्य अरावली की आज की

कहानी में 'इतिहास का फॉरेंसिक सबूत' जोड़ते हैं।

किस कीमत पर विकास

पारिस्थितिकी का टूटना अक्सर श्धीरेश होता है, पर जब वह दिखाई देता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरावली से बाघ का गायब होना सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं थाय वह जंगल के पूरे पिरामिड का ढहना था और वह ढहना पानी, मिट्टी, खेती और समाज तक फैलता है। सरकारी तंत्र और अदालती आदेशों के द्वंद्व में अरावली का भविष्य फंसा है, जहां श्रविकासर की भाषा अक्सर श्रभूगोलर को म्यूट कर देती है। अरावली के छीजने की मानवीय लागत अकल पनीय है। चरवाहे, किसान और शहर की सीमा पर रहने वाले लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन आजकल अरावली क्षेत्र के पुराने चरवाहे यह साफ महसूस करते हैं कि गर्मी तेज हुई है, क्योंकि हरियाली घट गई है। बारिश का पानी जल्दी बह जाता है, क्योंकि ढलानों पर कटाव बढ़ा है। पशुओं के चरने का क्षेत्र कम हुआ है। और कई जगहों पर श्रजंगलर का अर्थ अब सुरक्षा नहीं, टक. राव बन गया हैय क्योंकि आवास टूटने पर वन्यजीव और मनुष्य एक ही संकरे भू-भाग में आ जाते हैं। यह कहानी केवल श्रपर्यावरण बनाम विकास नहीं है। यह किस कीमत पर विकास का सवाल है और किसके हिस्से में वह कीमत आती है। हालांकि अरावली पर एक भरोसेमंद उम्मीद की कहानी भी मौजूद है। जैसे पुनर्स्थापन। गुरुग्राम का अरावली बायोड.। यवर्सिटी पार्क अक्सर इस बात का उदा. हरण दिया जाता है कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त भू-भाग को भी नागरिक पहल, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और लंबे धैर्य से फिर से जीवित किया जा सकता है। ऐसी प. रयोजनाएँ यह संकेत देती हैं कि बहस केवल श्रबचानेश की नहीं हैय श्रबहाल करने की भी है। लेकिन बहाली का अर्थ सिर्फ पार्क बनाना नहींय इसका अर्थ कॉरिडोर जोड़ना, खनन-प्रबंधन को पारदर्शी बनाना, और शहर-योजना में पहाड़ को 'लैंड बैंक' नहीं, 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' मानना है। पर्यावरणविद टीआई खान बताते हैं कि अस्सी के दशक में



अरावली में सिर्फ 12 गैप थे, जो अब कई गुणा बढ़ गए हैं और इसे लेकर तत्कालीन पर्यावरण सचिव टीएन शेषन बहुत चिंतित थे, क्योंकि दिल्ली की तरफ रेगिस्तान बढ़ रहा था। उन्होंने उस समय सैंड ड्यून ऐश्टेब्लाइजेशन डिपार्टमेंट बनवाया था। मेवाड़ के बाघों का अंत, जिसे एमके रंजीतसिंह ने संख्याओं में दर्ज किया, एक चेतावनी है कि जंगल का पतन सिर्फ जंगल का पतन नहीं हो. ताय वह शासन, समाज और भविष्य का पतन भी बन सकता है। अरावली उत्तर भारत की ढाल हैय क्योंकि यह हवा को थामती है, पानी को उतारती है और जीवन को जोड़ती है। सवाल यह नहीं कि अरावली श्रकितनी पुरानी है। सवाल यह है कि हम उसे श्रकितनी देर तक जीवित रहने देंगे और किस कीमत पर।

अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था उस पर रोक लगा दी है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर जाँच की जरूरत है। पीठ ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर पहले बनी सभी समि. तियों की सिफारिशों का आकलन करने के लिए एक नई उच्चस्तरीय समिति गठित

करने का प्रस्ताव भी दिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से भी कहा है कि वे प्रस्तावित समिति की संरचना समेत इस मामले में अदालत की सहायता करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि समिति की सिफारिशें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष फिलहाल स्थगित रहेंगे। इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। फैसले के बाद अरावली वि. रासत जन अभियान की संयोजक नीलम अहलूवालिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा के प्रभाव पर विस्तृत स्वतंत्र अध्ययन का आदेश दिया है। अरावली संरक्षण की मांग को लेकर जन आंदोलन जारी रहेगा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था। उसके अनुसार आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर (328 फीट) ऊँचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा।



दो या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियाँ, जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हों और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली शृंखला का हिस्सा माना जाएगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि सिर्फ ऊँचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करने से कई ऐसी पहाड़ियों पर खनन और निर्माण के लिए दरवाजा खुल जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो 100 मीटर से छोटी हैं, झाड़ियों से ढँकी हुई और पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। हालाँकि केंद्र सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एकरूपता लाना है, न कि सुरक्षा को कम करना।

लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?

इस मामले को लेकर बीते हफ्ते गुरुग्राम और उदयपुर समेत कई शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। इनमें स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ जगहों पर वकील और राजनीतिक दल भी शामिल हुए। पीपल फॉर अरावलीज समूह की संस्थापक सदस्य नीलम आहलूवालिया ने कहा कि नई परिभाषा अरावली की अहम भूमिका को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल को रीचार्ज करने और लोगों की आजीविका बचाने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी-छोटी झाड़ियों से ढँकी पहाड़ियाँ भी रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल रीचार्ज करने और

स्थानीय लोगों के रोजगार में अहम योगदान देती हैं। अरावली बचाने के आंदोलन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़ कहते हैं, अरावली को सिर्फ ऊँचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों और पहाड़ी प्रणालियाँ की पहचान उस काम से होती, जो उनके होने से संभव होते हैं न कि ऊँचाई के किसी मनमाने पैमाने से। वह कहते हैं, जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण या रेगिस्तान बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊँचाई कितनी भी हो। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सरकार अरावली क्षेत्रों को वैज्ञानिक मानकों से परिभाषित करे, जिसमें उसका भूगोल, पर्यावरण, वन्यजीव संपर्क और जलवायु संघर्ष क्षमता शामिल हो। टोंगड़ चेतावनी देते हैं कि अदालत की नई परिभाषा से खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस मामले में अपनी आवाज तेज कर दी है। उनका कहना है कि नई परिभाषा से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली

की रक्षा को शिदल्ली का अस्तित्व बचाने से अलग नहीं किया जा सकता। राजस्थान कांग्रेस के नेता टीका राम जुल्ली ने अरावली को राज्य की 'जीवन रेखा' बताया और कहा कि अगर यह न होती तो 'दिल्ली तक का पूरा इलाका रेगिस्तान बन गया होता।'

सरकार का क्या कहना है?

बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने इस मामले में एक बयान जारी किया था। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में गया कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एकरूपता लाना है। बयान में यह भी कहा गया था कि खनन को सभी राज्यों में समान रूप से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा जरूरी थी। इसमें जोड़ा गया था कि नई परिभाषा पूरे पहाड़ी तंत्र को शामिल करती है, जिसमें ढलानें, आसपास की जमीन और बीच के इलाके शामिल हैं ताकि पहाड़ी समूहों और उनके आपसी संबंधों की सुरक्षा हो सके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली हर जमीन पर खनन की इजाजत होगी। सरकार का कहना था कि अरावली पहाड़ियों या शृंखलाओं के भीतर नए खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे तभी जारी रह सकते हैं, जब वे टिकाऊ खनन के नियमों का पालन करें। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि अभेद्य क्षेत्रों, जैसे कि संरक्षित जंगल, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और आर्द्रभूमि में खनन पर पूरी तरह रोक है। हालाँकि इसका अपवाद कुछ विशेष, रणनीतिक और परमाणु खनिज हो सकते हैं, जिसकी अनुमति कानूनन दी गई हो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली शृंखला का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वह भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। हालाँकि, विरोध कर रहे कई समूहों ने कहा था कि प्रदर्शन जारी रहेंगे और वे अदालत की नई परिभाषा को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं।

इंदौर : दूषित पानी से मौतों से भारत का सबसे साफ शहर होने के दावे पर उठे सवाल?

इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत



श्वेतांक वर्मा
मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई दर्जन भर ज्यादा लोगों की मौत के बाद इंदौर शहर के भारत का सबसे साफ शहर होने के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया है कि ये मौतें किन वजहों से हुई है इनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इंदौर भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में लगातार आठ बार से नंबर वन पायदान पर आ रहा है। लेकिन बीते हफ्ते इंदौर में दूषित पानी से ऐसा संकट पैदा हुआ कि करीब 400 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जबकि 150 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद ये सवाल सबसे ज्यादा खड़ा हुआ कि आखिर देश के सबसे स्वच्छ शहर में पानी का ये संकट पैदा कैसे हुआ? शुरुआती जांच में मालूम चला कि भागीरथपुरा में जिस टंकी का पानी सप्लाई होता है, उसी के पास बनी पुलिस चौकी के टॉयलेट के आउट फॉल्स का दूषित पानी, सप्लाई वाली पाइपलाइन में मिस हो गया। इंदौर शहर पूरे देश के लिए एक मिसाल

बना हुआ था और इस शहर की सफाई की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। शहर की सड़कों की रात में सफाई की जाती है। शहर में बेहतर तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। इंदौर के घरों में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग रखा जाता है। यही वजह है कि इंदौर भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में लगातार आठ बार से नंबर वन आया। साल 2025 के सर्वे में इंदौर के साथ गुजरात के सूरत शहर को स्वच्छ भारत अभियान में नंबर वन चुना गया।

पीने के पानी में मिला शौचालय का दूषित जल

इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, शुरुआती जांच में पाया गया है कि भागीरथपुरा की नर्मदा जल की पानी की टंकी जो पुलिस चौकी के पास ही है। वहां पुलिस चौकी की टॉयलेट के ड्रेन पाइप का दूषित पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल रहा था। इसे अब ठीक कर दिया गया है। आगे भी जांच चल रही है, कहीं कुछ और पाया जाता है तो उसे भी ठीक किया जाएगा। शिवम वर्मा ने कहा, प्यहानगर निगम के जो जोनल अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। आगे ऐसा कुछ न हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा,

हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उल्टी-दस्त की बीमारी के जो भी मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। साफ पानी की सप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है।

अगर समय पर पानी का टेस्ट होता तो ये त्रासदी नहीं होती

सुधींद्र मोहन शर्मा पूर्व नेशनल नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा रहे हैं। वो बताते हैं, इंदौर की सफाई बाहर से दिखती है। हम झाड़ू कितनी बार लगा रहे हैं, उस्ट कितनी साफ कर रहे हैं, टॉयलेट कितने बना रहे हैं? इसके आंकड़े कहाँ हैं। कचरे के ढेर को भी मिट्टी के ढेर से ढंका जा रहा है और सफाई में नंबर वन बन गए हैं।

सुधींद्र मोहन शर्मा सवाल करते हैं कि साफ पानी हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, पानी हमारी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि क्लीनेस्ट सिटी की रैंकिंग में साफ पानी का हिस्सा 7 से 8 फीसदी ही है। पीने का पानी कितना घातक है, इसे नापा ही नहीं गया है। सुधींद्र मोहन शर्मा कहते हैं, सफाई में जितना काम किया गया वह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन इंदौर में वॉटर क्वालिटी सर्विलांस और मॉनिटरिंग पर नगर निगम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वॉटर क्वालिटी सर्विलांस का मतलब यह होता है कि सिर्फ वॉटर क्वालिटी चेक नहीं करना है आपको उस वॉटर क्वालिटी को रिकॉर्ड भी करना है। इसका लगातार एनालिसिस करते रहना है। जो भारत सरकार के मैनुअल्स हैं, उसके हिसाब से इंदौर में कम से कम दस सैंपल हर दिन लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा करने पर अलग-अलग इलाकों में एक महीने में पूरा इंदौर कवर हो जाएगा। पूरे इंदौर शहर को कवर करने के लिए 300 से ज्यादा सैंपल लिए जाने की जरूरत है। ऐसा करके ही दूषित पानी का पता



लगाया जा सकता है।

पानी की समस्या का समाधान अभी भी नहीं

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की समस्या का निदान अभी भी नहीं हुआ है। पूरे इलाके में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। बीते हफ्ते हुई त्रासदी में दूषित पानी से सबसे ज्यादा समस्या बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को हुई। 19 साल की प्रियांशी बागो रिया छह महीने की गर्भवती हैं। उन्हें 25 दिसंबर को उल्टी दस्त की शिक। यत हुई। दस्त नहीं रुकने पर उन्हें 27 दिसंबर को एमटीएच अस्पताल में भर्ती किया गया और दो जनवरी को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रियांशी के पति अभिनव बागोरिया ने बताया, पत्नी अलग-अलग अस्पताल वालों ने पहले इलाज नहीं किया। सबसे पहले हम निजी अस्पताल त्रिवेणी पहुंचे वहाँ बताया गया कि इलाज में 15 से 20 हजार रुपये का खर्च आएगा। हम ये खर्च नहीं उठा सकते थे। फिर सरकारी बीमा लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब भी इलाज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कार्ड होगा तो ही इलाज होगा, फिर एक और सरकारी एमवाय अस्पताल गए। वहाँ भी इलाज नहीं हुआ। हमें कहा गया कि गर्भवती महिला का एमटीएच अस्पताल में इलाज होगा। अभिनव ने कहा, उस अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। पिता का पहले से वहाँ इलाज चल रहा था। मेरे पिता

ई-रिक्शा चलाते हैं। जांच में आए 8 से 10 हजार रुपये का खर्च चाचा की मदद से उठाया।

दूसरे इलाकों में भी पानी की समस्या इंदौर के भागीरथपुरा के अलावा दूसरे इलाकों से भी पानी खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। खंडवा नाका भावना नगर लिंबोदी के वॉर्ड 75 और 77 की ड्रेनेज पाइपलाइन का काम दो-तीन दिन से चल रहा है। इस इलाके के लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ बोरिंग से पानी आ रहा है और ड्रेनेज का पानी बोरिंग में मिल जाता है। इलाके के हैंडपंप भी दूषित पानी की सच्चाई को बयां करते हैं। वहाँ रहने वाले दीपक ने हमारे सामने हैंडपंप चलाकर दिखाया कि कितना खराब पानी आ रहा है। दीपक ने उस हैंडपंप से पानी की बाल्टी भरी तो उसमें मिट्टी के जैसा गंदा पानी था। दीपक ने कहा, फर्क बार इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

इंदौर जल त्रासदी पर नकी सख्त टिप्पणी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में बेहद तलख टिप्पणी की है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा, बहुत दुखद है। देश ही नहीं विदेश

तक में शहर की छवि बिगड़ी है। देश का नाम खराब हो रहा है। कोर्ट में मामले पर यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ इंदौर नहीं पूरे प्रदेश का है। हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव इस मामले में खुद शासन का पक्ष कोर्ट के सामने रखें। वे अगली सुनवाई पर वीसी से उपस्थित हो सकते हैं। मामले से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि खबरें बता रही हैं कि पूरे शहर में दूषित पानी वितरित हो रहा है। यह चिंता का विषय है।

बदले गए नगर निगम कमिशनर, क्षितिज सिंघल को दी जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले ने देशभर के लोगों का ध्यान खींच रखा है। ऐसे में नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद राज्यपाल के आदेशानुसार मुख्य सचिव की ओर से नगर निगम आयुक्त को बदल दिया गया है। मुख्य सचिव ने क्षितिज सिंघल को नया निगम कमिशनर बनाने के निर्देश दिए हैं। घटना को देखते हुए पूर्व नगर निगम कमिशनर दिलीप कुमार यादव को हटाया गया। जिसके बाद यह जिम्मेदारी अब क्षितिज सिंघल को दी गई।

सीएम ने दिए थे दिलीप कुमार को हटाने के आदेश

लोगों की मौत के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगर निगम के पद पर तैनात दिलीप कुमार यादव को हटाने के निर्देश दिए थे। सीएम द्वारा सोशल मीडिया के जरिए इसकी सूचना दी गई थी। बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत के मामले ने झकझोर दिया है। इसको देखते हुए सरकार की ओर से यह एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में हुई इस घटना को लेकर 16 नगर निगमों के मेयर, अध्यक्ष और कमिशनर के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। साथ ही अन्य अधिकारियों को सख्ती से निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

उत्तराखंड में नस्लीय टिप्पणी के विरोध पर त्रिपुरा के छात्र की हत्या, पूरे देश में गूंजा मामला



सुनील नेगी उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में नस्लीय टिप्पणी के विरोध के बाद एक आदिवासी छात्र पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र का शव जब त्रिपुरा पहुंचा, तो पूरे राज्य में आक्रोश और शोक का माहौल बन गया। मृतक की पहचान अंजेल चकमा के रूप में हुई है, जो त्रिपुरा का रहने वाला था। अंजेल देहरादून स्थित जिज्ञासा विश्वविद्यालय में एमबीए के अंतिम वर्ष का छात्र था। हमले के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और कई दिनों तक अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी से जूझता रहा, लेकिन आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, 9 दिसंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच देहरादून के सेलाकुई इलाके में अंजेल अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ किराने का सामान लेने गया था। इसी दौरान शराब के नशे में कुछ लोगों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां कीं और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर हमलावरों ने मारपीट शुरू कर दी। माइकल के सिर पर वार किया गया,

जबकि अंजेल की गर्दन और पेट में चाकू मारा गया। गंभीर हालत में अंजेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।

अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़

अंजेल का पार्थिव शरीर दिल्ली के रास्ते अगरतला लाया गया। महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा पर परिजन और कई नेता मौजूद रहे। वहां से शव को अंजेल के पैतृक गांव उनाकोटी ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार से पहले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए।

केंद्र से हस्तक्षेप की मांग

अंजेल की मौत के बाद परिजनों और विभिन्न छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों व हिंसा की घटनाओं पर सख्त कदम उठाने की अपील की है।

पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए : किरेन रिजिजू

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की जरूरत

पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने मामले में तेजी से कार्रवाई की है और अब तक करीब पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती थीं, खासकर दिल्ली में। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के समय 20 से 40 घटनाएं आम थीं, लेकिन दिल्ली में विशेष इकाई बनाए जाने के बाद ऐसी घटनाओं में कमी आई है। रिजिजू ने नस्लवाद को एक 'वैचारिक बीमारी' बताया और कहा कि ऐसी सोच कुछ ही लोगों में होती है, जिसे जागरूकता के जरिये दूर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता केवल कुछ लोगों में होती है और इसके खिलाफ जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में नस्लवाद और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी जाति, नस्ल या धर्म के लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल पूर्वोत्तर के लोग ही नहीं, बल्कि सभी को इस तरह की घटनाओं से दुखी होना चाहिए, क्योंकि यह किसी के साथ

भी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतिहास में लोगों को भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह नस्लवाद का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज भी विदेश में श्वेत रंग के नहीं होने पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यह देश के भीतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है।

फरार आरोपी पर घोषित किया 25

हजार रुपए का इनाम

उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, एमबीए के छात्र एंजेल चकमा पर नौ दिसंबर को देहरादून में कुछ लोगों ने चाकू और अन्य हथियारों से हमला किया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से दो ना बालिग हैं और उन्हें सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, फरार आरोपी की तलाश में एक पुलिस टीम नेपाल भी भेजी गई है।

नफरत नहीं, नशे और गलतफहमी में गई जान : पुलिस

देहरादून पुलिस ने एंजेल चकमा की हत्या के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ पेश किया है। जहां एक तरफ मृतक का परिवार और पूर्वोत्तर के संगठन इसे 'हेट क्राइम' और 'नस्लीय हिंसा' बता रहे हैं, वहीं पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में नस्लीय कोण होने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि यह घटना नशे की हालत में हुई गलतफहमी का नतीजा थी, न कि किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा। उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट किया कि एंजेल चकमा की मौत के मामले में अब तक की जांच में कोई नस्लीय एंगल सामने नहीं आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की तह तक जाने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने अपने दावे को पुष्टा करने के लिए एक अहम तर्क दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांच

आरोपियों में से एक व्यक्ति खुद मणिपुर का रहने वाला है। पुलिस का तर्क है कि जब हमलावर गुट में खुद पूर्वोत्तर का व्यक्ति शामिल है, तो यह कहना मुश्किल है कि यह हमला पूर्वोत्तर के छात्रों को निशाना बनाकर किया गया 'नस्लीय अपराध' था। पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो गुटों के बीच अचानक हुई मारपीट का नतीजा थी, न कि किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत का प्रदर्शन।

पुलिस की थ्योरी

एसएसपी अजय सिंह ने घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए बताया कि 9 दिसंबर की रात को असल में क्या हुआ था। पुलिसिया जांच के मुताबिक, यह पूरा मामला एक 'बर्थडे पार्टी', शराब और गलतफहमी के इर्द-गिर्द घूमता है। आरोपियों में से एक ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों को बुलाया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी पक्ष ने घटना से पहले शराब पी रखी थी और वे नशे की हालत में थे। पुलिस का दावा है कि आरोपी आपस में ही बातचीत कर रहे थे और एक-दूसरे पर मजाक-मजाक में फटियां कस रहे थे। उसी वक्त वहां से एंजेल चकमा और उसका भाई माइकल गुजर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जो कमेंट्स किए, वे उनके अपने दोस्तों के लिए थे। लेकिन एंजेल और माइकल को लगा कि वे कमेंट्स उन पर किए गए हैं। इस गलतफहमी के चलते एंजेल चकमा ने हस्तक्षेप किया और आरोपियों को टोक दिया। चूंकि आरोपी नशे में थे, इसलिए बात बढ़ गई। बहस ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और मारपीट शुरू हो गई। एसएसपी ने कहा, पूछताछ के दौरान कई तरह की जानकारीयां सामने आई हैं। यह बात प्रकाश में आई है कि मणिपुर का रहने वाला एक आरोपी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उस दौरान उन्हा-ने आपस में ही कुछ टिप्पणियां कीं। इन टिप्पणियों को पीड़ित पक्ष ने अपने ऊपर ले लिया और रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद हुआ।

परिवार के दावों से सीधा विरोधाभास

पुलिस का यह बयान एंजेल के भाई माइकल चकमा और पिता के बयानों से बिल्कुल अलग है। याद दिला दें कि एंजेल के पिता तरुण चकमा, जो बीएसएफ में

तैनात हैं। उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमलावरों ने उनके बेटों को चाइनीज और चाइनीज मोमो कहकर बुलाया था। माइकल का भी आरोप था कि जब उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, तो हमलावरों ने उन पर और बेरहमी से हमला किया। लेकिन पुलिस की गलतफहमी वाली थ्योरी ने इस मामले को एक नई दिशा दे दी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आरोपी खुद नॉर्थईस्ट का था, तो क्या वाकई वहां चाइनीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, या यह शराब के नशे में हुआ महज एक झगड़ा था?

सीएम धामी ने मृतक के पिता से की बात, सख्त सजा का आश्वासन दिया

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हुई हत्या के बाद उपजे आक्रोश के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उसके पिता से फोन पर बातचीत कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया और राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत करते हुए चार लाख रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी। पुलिस ने कहा कि चकमा की मौत उसकी रीढ़ की हड्डी और सिर में लगी घातक चोट की वजह से हुई। धामी ने एंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बातचीत कर उसकी हत्या पर दुरुख व्यक्त किया और कहा कि इस घटना से वह व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं और उनके परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश-विदेश से बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहां कभी इस प्रकार का माहौल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इसलिए यह घटना हम सबके लिए भी कष्टदायक है। धामी ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने तरुण चकमा को जानकारी दी कि घटना के संबंध में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है और उस पर इनाम घोषित करते हुए उसे भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घटना के संबंध में उनकी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात हुई है।

धामी ने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि परिवार की सहायता के लिए वह डॉ. साहा से बातचीत करेंगे और साथ ही उत्तराखंड सरकार भी परिवार की हरसंभव सहायता करेगी। यहां के एक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए अंतिम वर्ष के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा को नौ दिसंबर को कुछ युवकों द्वारा कथित तौर पर चाकू और कड़े से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। अस्पताल में 17 दिन तक भर्ती रहने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गयी थी इस बीच, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत करते हुए पहली किस्त के रूप में 4,12,500 रुपये का चेक भेज दिया। पीड़ित परिवार को यह आर्थिक सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत स्वीकृत की गई है। बाद में यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने एंजेल चकमा की नृशंस हत्या को अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का असमय अंत है। उन्होंने एंजेल के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उसके पिता से बातचीत में उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके बेटे के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। धामी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक शांत, समावेशी और सौ. हार्दपूर्ण राज्य है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक कोने से आने वाले छात्र यहां सुरक्षित महसूस करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में अध्ययनरत पूर्वोत्तर सहित सभी बाहरी राज्यों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ठोस और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच, पुलिस ने बताया कि एंजेल चकमा की मौत उसकी रीढ़ की

हड्डी एवं सिर में घातक चोट लगने की वजह से हुई। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने कहा कि एंजेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार को मिल जाएगी लेकिन उसकी मौत की वजह स्पष्ट रूप से उसकी रीढ़ की हड्डी एवं सिर में घातक चोट लगना है। उन्होंने बताया कि एंजेल की अन्य मेडिकल रिपोर्टें मिल चुकी हैं। एंजेल की हत्या में कथित रूप से शामिल छह आरोपियों में से पांच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला यज्ञराज अवस्थी फरार है जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। पांच में से दो आरोपी नाबालिग हैं जबकि गिरफ्तार तीन आरोपियों की पहचान फिलहाल देहरादून में रह रहे मणिपुर निवासी सूरज ख्वास (22) अविनाश नेगी (25) और सुमित (25) के रूप में हुई है।

उत्तराखंड में नस्लभेद के चलते छात्र की हत्या बेहद हृदयविदारक : केजरीवाल

भाजपा शासित उत्तराखंड के देहरादून में नस्लभेद के चलते हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल त्रिपुरा के छात्र की दुखद मौत पर आम आदमी पार्टी ने गहरी चिंता जताई है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्र की मौत को बेहद चौंकाने वाला और हृदयविदारक बताया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा निवासी एमबीए छात्र की देहरादून में सिर्फ उसकी पहचान के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एमबीए छात्र की हत्या न सिर्फ एक अपराध है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक कलंक है। ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ देश को एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। एक्स पर देहरादून में नस्लभेद के चलते त्रिपुरा के छात्र की हत्या की खबर को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह खबर बेहद चौंकाने वाली और हृदयविदारक है। त्रिपुरा के एक युवा एमबीए छात्र की देहरादून में सिर्फ उसकी पहचान के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक कलंक है। अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि देश को नस्लवाद और घृणित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता

है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय त्वरित और मिसाल कायम करने वाला होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा शासित उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की हत्या कर दी गई। इस छात्र की हत्या इसलिए हुई, क्योंकि उसने नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया और हमलावरों को नस्लीय टिप्पणी करने से मना किया। जिसके बाद हमलावरों ने अंजेल चकमा को सरेआम सड़क पर पीटा और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई।

नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम : अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के नंदननगर के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा को नौ दिसंबर को देहरादून में एक समूह ने कथित रूप से नस्लीय अपशब्द कहे, जिसका विरोध करने पर उसपर हमला कर दिया गया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, यादव ने कहा कि विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेली की तरह फलफूल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता-अखंडता खतरे में है। यादव ने कहा कि आज इन हिंसक हालात में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब शान्ति प्रिय, सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें, नहीं तो हममें से कोई भी कल इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा।

कोल इंडिया को बीसीसीएल आईपीओ में 10 फीसदी हिस्सेदारी से कमाएगी 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट



कोलकाता। सरकारी माइनर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में आने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 10 परसेंट हिस्सेदारी बेचकर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट कमाएगा। यह बात ऑफर डॉक्यूमेंट में कही गई है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, बीसीसीएल के शेयरों को खरीदने की कोल इंडिया की वेटेड एवरेज कॉस्ट 10 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 21-23 रुपये प्रति शेयर तय होने के साथ, माइनर कंपनी को बेची जा रही हिस्सेदारी पर 12-13 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे पर, कोल इंडिया को आईपीओ से लगभग 1,071 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो 100 परसेंट ऑफर फॉर सेल इश्यू है। लगभग 466 करोड़ रुपये की

एक्विजिशन कॉस्ट को जोड़ने के बाद, नेट गेन लगभग 605 करोड़ रुपये होता है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर लगभग 130 परसेंट का रिटर्न देता है। बीसीसीएल की लिस्टिंग, कोल इंडिया की बड़ी सब्सिडियरी कंपनियों के प्लान किए गए डाइवैस्टमेंट की सीरीज में पहली है और 2026 का पहला मेनबोर्ड इश्यू भी है। बीसीसीएल ने कहा कि प्रपोज्ड प्लान का मकसद कोल इंडिया की सब्सिडियरी में वैल्यू अनलॉक करना है। बीसीसीएल की लिस्टिंग, कोल इंडिया की अपनी खास सब्सिडियरी कंपनियों को मोनेटाइज करने के बड़े प्लान का हिस्सा है। कंपनी के बोर्ड ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड समेत दूसरी कंपनियों के आईपीओ को पहले ही मंजूरी दे दी है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9 जनवरी को खुलेगा और 13 जनवरी को बंद होगा, और शेयर बीएसई और एनएसई पर 16 जनवरी, 2026 को लिस्ट होंगे। क्योंकि यह इश्यू पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, इसलिए बीसीसीएल को आईपीओ से कोई इनकम नहीं मिलेगी, और पूरी रकम कोल इंडिया को मिलेगी। अनऑफिशियल ग्रे मार्केट में, बीसीसीएल के शेयर संभावित इश्यू प्राइस से 13.5-14 के प्रीमियम पर चल रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि सब्सिडियरी लिस्टिंग को लेकर उम्मीदों ने पिछले पांच दिनों में कोल इंडिया के स्टॉक को 6.29 परसेंट की बढ़त के साथ 426 रुपये प्रति शेयर पर सपोर्ट दिया है।

गेल गैस ने की सीएनजी और घरेलू पीएनजी कीमतों में 1 रुपए की कटौती



नई दिल्ली। गेल गैस लिमिटेड ने गुरुवार को सीएनजी की कीमत और खाना पकाने के लिए घरों की रसोई में पाइप से भेजी जाने वाली नैचुरल गैस की कीमत में 1 रुपये की कमी की घोषणा की। यह कदम दूसरे सिटी गैस रिटेलर्स द्वारा कीमतों में कटौती के बाद उठाया गया है। यह घोषणा भारत के सबसे बड़े सिटी गैस रिटेलर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा दिल्ली और एनसीआर के शहरों में खाना पकाने के लिए घरों की रसोई में पाइप से भेजी जाने वाली नैचुरल गैस की कीमतों में 0.70 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती के एक दिन बाद आई है। इससे पहले, थिंक गैस ने सीएनजी की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति 16 और घरेलू पाइप नैचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में 5 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (बउ) तक की कटौती की थी। सभी अधिकृत क्षेत्रों में 1 रुपये की कमी। फर्म ने एक बयान में कहा कि गेल गैस लिमिटेड ने देश में अपने सभी अधिकृत क्षेत्रों में घरेलू पाइप नैचुरल

गैस (पीएनजी) और कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) की कीमत में क्रम से 1 रुपये प्रति बउ और 1 रुपये प्रति 16 की कमी की है। कई राज्यों में कीमत में कटौती लागू। यह कीमत कटौती गुरुवार से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा में गेल गैस के ज्योग्राफिकल एरिया (छो) में लागू होगी। पाइपलाइन टैरिफ को बेहतर बनाने का जिम्मा इस फैसले पर बात करते हुए, गेल गैस के एक अधिकारी ने कहा कि पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय और सेक्टर रेगुलेटर पेट्रोलियम और नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड लगातार प्रोग्रेसिव पॉलिसी उपाय लागू कर रहे हैं, जो भारत में सीएनजी और घरेलू पीएनजी मार्केट की ग्रोथ के लिए एक अच्छा और फाइनैशियली टिकाऊ इकोसिस्टम बना रहे हैं।

आरईसी ने 47वें ऑल इंडिया पीआर कॉन्फ्रेंस में दो अवॉर्ड जीते

देहरादून। हाल ही में देहरादून में पब्लिक रिलेशंस साइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा आयोजित 47वें ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में आरईसी लिमिटेड को दो प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। आरईसी लिमिटेड को पब्लिक रिलेशंस और इन-हाउस जर्नल कैटेगरी में अवॉर्ड मिले, जिसमें स्टेकहोल्डर कम्युनिकेशन को मजबूत करने, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने, और स्ट्रक्चर्ड और भरोसेमंद कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के जरिए अपने इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स को असरदार तरीके से पेश करने में ऑर्गनाइजेशन की लगातार कोशिशों को पहचान मिली। ये अवॉर्ड पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के



पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर श्रीमती रितु खंडूरी भूषण ने दिए। कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही के दौरान हुए अवॉर्ड सेरेमनी में आरईसी लिमिटेड, देहरादून ऑफिस के सीपीएम सुनील बिष्ट और आरईसी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम के सदस्यों ने ये अवॉर्ड लिए। कॉन्फ्रेंस के दौरान, आरईसी की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम ने 'पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की भूमिका' पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें पब्लिक सेक्टर के संगठनों में ट्रांसपेरेंसी, भरोसा और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में कम्युनिकेशन की बदलती स्ट्रेटेजिक भूमिका पर जोर दिया गया। ये अवॉर्ड्स आरईसी के पब्लिक रिलेशंस के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच, अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ इसके लगातार जुड़ाव, और इसके इन-हाउस जर्नल की क्वालिटी और रिलिबेंस को दिखाते हैं, जो इंटरनल कम्युनिकेशन, एम्प्लॉई एंगेजमेंट, और ऑर्गनाइजेशन के विजन और वैल्यूज के हिसाब से जानकारी फैलाने में अहम भूमिका निभाता है। ऑल इंडिया पीआर कॉन्फ्रेंस, पीआरएसआई का खास सालाना इवेंट है। यह नए ट्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिस और गवर्नेंस, बिजनेस और समाज में पब्लिक रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बदलती भूमिका पर चर्चा के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म देता है।

सहज और एलआईसी ने मिलकर भारत के लाखों वंचित लोगों के लिए बीमा की सुविधा शुरू



नई दिल्ली। एक कॉर्पोरेट एजेंट, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज ने शुक्रवार को कहा कि उसने देश के ग्रामीण और सेमी-अर्बन हिस्सों में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) के साथ टाई-अप किया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस कोलेबोरेशन के तहत, कनोरिया फाउंडेशन की कंपनी सहज का असिस्टेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक एक्सेस को आसान बनाएगा, जिससे नागरिक पॉलिसीज को समझ सकें, उनमें एनरोल कर सकें और उन्हें मैनेज कर सकें, खासकर उन इलाकों में जहाँ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस ट्रेडिशनली कम रही है। एलआईसी की भरोसेमंद लेगेसी को सहज की लास्ट-माइल रीच और असिस्टेड डिजिटल मॉडल के साथ मिलाकर, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मकसद यह पक्का करना है कि भारत के लिए इंश्योरेंस आसान, ज्यादा एक्सेसिबल और सच में इनक्लूसिव हो जाए, ऐसा उसने कहा। इस कोलेबोरेशन से अवेयरनेस में सुधार, पॉलिसी सर्विसिंग

को मजबूत करने और लाइफ इंश्योरेंस को ज्यादा अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत के बड़े फाइनेंशियल इनक्लूजन और सोशल सिविलिटी ऑब्जेक्टिव्स में कट्रीब्यूट होगा, ऐसा उसने कहा। सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, सहज रिटेल की पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी है और कनोरिया फाउंडेशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। कंपनी को हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिला है, जिससे वह पूरे देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। कंपनी के मुताबिक, सहज लगभग 4.5 लाख डिजिटली इनेबल्ड ग्रामीण सेंटर्स के नेटवर्क के जरिए काम करता है, जो मिलकर 70 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को सर्विस देते हैं। इंश्योरेंस वर्टिकल को सस्ते और आसानी से समझ में आने वाले प्रोडक्ट्स देने के लिए बनाया गया है, जिन्हें ट्रेंड सहज मित्र सपोर्ट करते हैं जो कस्टमर्स को ऑनबोर्डिंग, सर्विसिंग और क्लेम में मदद करते हैं। सहज सेंटर्स फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाने की कोशिशों के तहत, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस ऑफरिंग के साथ-साथ सरकार द्वारा सपोर्टेड इंश्योरेंस और सोशल सिविलिटी स्कीम्स तक एक्सेस भी आसान बनाएंगे।

एसजेवीएन को राजस्थान में 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की सीओडी हासिल



एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने अवगत कराया है कि एसजेवीएन ने आज राजस्थान के 1000 मेगावाट क्षमता वाले बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) सफलतापूर्वक हासिल की है। यह उपलब्धि देश की विद्युत उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री गुप्ता ने इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता न सिर्फ एसजेवीएन की तकनीकी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है, अपितु कर्मचारियों, ठेकेदारों और सभी स्टैकहोल्डर्स के समर्पण और समन्वित प्रयासों को भी दर्शाती है। श्री गुप्ता ने आगे बताया कि 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान के बीकानेर जिले में अवस्थित है और इसे एसजेवीएन अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना प्रचालन के प्रथम वर्ष में 2,454.55 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न करेगी और 25 वर्षों में कुल मिलाकर लगभग 56,838 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न करेगी। अधिकतम उपयोग शुल्क ₹2.57 प्रति यूनिट तय किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती ग्रीन ऊर्जा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा की राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों को आपूर्ति की जाएगी। अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक) ने इसमें शामिल सभी कार्मिकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की और बताया कि यह परियोजना राजस्थान के बीकानेर जिले में बांदरवाला गांव के समीप पूर्ण रूप से खरीदी गई 5,000 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। यह देश के सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी वाले इलाकों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना की कमीशनिंग से भारत सरकार के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सिपन कुमार गर्ग निदेशक (वित्त) एसजेवीएन ने कहा कि यह परियोजना ₹5,492 करोड़ की लागत से बनाई गई है और इसे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (डीसीआर) मोड के तहत पूरा किया गया है, जिसमें देश में बने सोलर फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिला है। ग्रिड को स्वच्छ ऊर्जा देने के अलावा, इस परियोजना से अनुमानित 27,85,077 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे पूर्व, राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिनांक 3 जनवरी 2023 को जयपुर, राजस्थान में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना दृ फेस ५, ट्रेच ५ के तहत विकसित किया गया है। डीसीआर मोड के तहत लागू होने से स्वदेशी सौर विनिर्माण इकोसिस्टम को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है।

प्रस्तुति-ग्राइम स्पेक्टोर डेस्क.



आरईसी ने 5वें पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 में प्रमुख सम्मान हासिल किए



नई दिल्ली। एक कॉर्पोरेट एजेंट, सहज इश्योरेंस सर्विसेज ने शुक्रवार को कहा कि उसने देश के ग्रामीण और सेमी-अर्बन हिस्सों में इश्योरेंस प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइफ इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) के साथ टाई-अप किया है। एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस कोलेबोरेशन के तहत, कनोरिया फाउंडेशन की कंपनी सहज का असिस्टेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क एलआईसी के लाइफ इश्योरेंस प्रोडक्ट्स और सवि. सेज तक एक्सेस को आसान बनाएगा, जिससे नागरिक पॉलिसीज को समझ सकें, उनमें एनरोल कर सकें और उन्हें मैनेज कर सकें, खासकर उन इलाकों में जहाँ इश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस ट्रे. डिशनली कम रही है। एलआईसी की भरोसेमंद लेगेसी को सहज

की लास्ट-माइल रीच और असिस्टेड डिजिटल मॉडल के साथ मिलाकर, सहज इश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मकसद यह पक्का करना है कि भारत के लिए इश्योरेंस आसान, ज्यादा एक्सेसिबल और सच में इनक्लूसिव हो जाए, ऐसा उसने कहा। इस कोलेबोरेशन से अवेयरनेस में सुधार, पॉलिसी सर्विसिंग को मजबूत करने और लाइफ इश्योरेंस को ज्यादा अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत के बड़े फाइनेंशियल इनक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट होगा, ऐसा उसने कहा। सहज इश्योरेंस सर्विसेज, सहज रिटेल की पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी है और कनोरिया फाउंडेशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। कंपनी को हाल ही में इश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिला है, जिससे वह पूरे देश में इश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। कंपनी के मुताबिक, सहज लगभग 4.5 लाख डिजिटली इनेबल्ड ग्रामीण सेंटर्स के नेटवर्क के जरिए काम करता है, जो मिलकर 70 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को सर्विस देते हैं। इश्योरेंस वर्टिकल को सस्ते और आसानी से समझ में आने वाले प्रोडक्ट्स देने के लिए बनाया गया है, जिन्हें ट्रेंड सहज मित्र सपोर्ट करते हैं जो कस्टमर्स को ऑनबोर्डिंग, सर्विसिंग और क्लेम में मदद करते हैं। सहज सेंटर्स फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाने की कोशिशों के तहत, लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस ऑफरिंग के साथ-साथ सरकार द्वारा सपोर्टेड इश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तक एक्सेस भी आसान बनाएंगे।

टाटा पावर ने भूटान की खोरलोचू हाइड्रो में 64 रुपए करोड़ लगाए, 40 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की



नई दिल्ली। टाटा पावर ने गुरुवार को खोरलोचू हाइड्रो पावर लिमिटेड (केएचपीएल) में 64 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। यह भूटान की कंपनी में 40 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने के एग्रीमेंट का हिस्सा है। अक्टूबर 2024 में, टाटा पावर ने केएचपीएल में एक या ज्यादा हिस्सों में 40 परसेंट इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया था। टाटा पावर ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम यह अपडेट देना चाहते हैं कि कंपनी ने अब लगभग 830 करोड़ रुपये के कुल इन्वेस्टमेंट में से तीसरे हिस्से के तौर पर 64 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 100 रुपये प्रति शेयर के 64 लाख

इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एक लीडिंग इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, जिसका 15.9 गेगावॉट का डायवर्सिफाइड एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें थर्मल, सोलर और विंड शामिल हैं। टाटा ग्रुप की यह कंपनी न्यूक्लियर स्पेस में भी डायवर्सिफाई करने पर विचार कर रही है। कंपनी न्यूक्लियर स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए जरूरी कानूनी बदलावों के बाद 20-50 मेगावाट कैपेसिटी के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स लगाने के बारे में पता लगाएगी **प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टोर डेस्क.**

पावरग्रिड और अफ्रीका 50 ने केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए पीपीपी समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक महारत्न पीएसयू, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने अफ्रीका 50 के साथ पार्टनरशिप में, केन्या में महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इसमें 400 केवी लेसॉस-लूसुक और 220 केवी किसुमु-काकामेगा-मुसागा ट्रांसमिशन सिस्टम शामिल हैं, जिसकी रियायत अवधि 30 साल है। इस एग्रीमेंट पर डॉ. आर. के. त्यागी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉ. यतींद्र द्विवेदी, डायरेक्टर (पर्सनल), और संजय कुमार गुप्ता, सीओओ (आईबी), पावरग्रिड, के साथ-साथ केन्याई सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, जिनमें श्री एलेक्स कामाऊ वाचिरो, सीबीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्टेट डिपार्टमेंट फॉर एनर्जी, डॉ. क्रिस के. किपटू, सीबीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द नेशनल ट्रेजरी, इंजीनियर किपकेमोई किबियास, एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, और इंजीनियर केफा सेडा, डायरेक्टर जनरल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स डायरेक्टोरेट शामिल हैं, की उपस्थिति में साइन किए गए। यह प्रोजेक्ट अफ्रीका का पहला इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट (आईटीपी) है और अफ्रीका में पावरग्रिड का पहला प्रोजेक्ट-फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रांसमिशन वेंचर है। प्रस्तावित ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को केन्या के नेशनल ग्रिड को मजबूत करने, सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार करने और रिन्यूएबल एनर्जी से भरपूर क्षेत्रों से प्रमुख लोड सेंटर्स तक बिजली पहुंचाने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइनें और संबंधित सबस्टेशन शामिल हैं। पीपीपी फ्रेमवर्क के तहत संरचित, यह प्रोजेक्ट अफ्रीका के पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अफ्रीका 50, जो अफ्रीकी सरकारों और अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्थापित एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, मजबूत क्षेत्रीय विशेषज्ञता और वित्तीय संरचना क्षमताओं को लाता है, जबकि पावरग्रिड बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन सिस्टम में अपने व्यापक तकनीकी, परिचालन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अनुभव का योगदान देता है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 25 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति के साथ, पावरग्रिड ने लगातार विविध और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन समाधान प्रदान करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। अफ्रीका 50 के साथ पावरग्रिड का सहयोग पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक विश्वसनीय वैश्विक भागीर के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। 15 दिसंबर 2025 तक, पावरग्रिड ने 287 सब-स्टेशन और 1,81,894 सीकेएम से अधिक ट्रांसमिशन लाइनें और 5,93,016 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता चालू की है और उनका संचालन कर रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स और टेक्निक्स को अपनाने, ऑटोमेशन और डिजिटल सॉल्यूशंस के बेहतर इस्तेमाल से, पावरग्रिड 99.84: से ज्यादा की औसत ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबिलिटी बनाए रखने में कामयाब रहा है।

एसजेवीएन की अध्यक्षता में नराकास का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह



एसजेवीएन लिमिटेड की अध्यक्षता में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), शिमला (कार्यालय-2) का वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह तथा छमाही बैठक का आयोजन एसजेवीएन लिमिटेड के परिसर में आज किया गया। इस अवसर पर चन्द्र शेखर यादव, कार्यकारी निदेशक (मा.सं.) सहित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन), कुमार पाल शर्मा तथा श्री आशीष पंत, महाप्रबंधक (राजभाषा) एसजेवीएन लिमिटेड उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्य-निष्पादन के लिए उन्हें नराकास राजभाषा शील्ड से सम्मानित भी किया गया। ये पुरस्कार श्री चन्द्र शेखर यादव, कार्यकारी निदेशक (मा.सं.) के करकमलों से प्रदान किए गए। कार्यालयों की संख्या के आधार पर पुरस्कारों को तीन श्रेणियों यथा सरकारी कार्यालय एवं वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम तथा बैंक श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो प्रोत्साहन

पुरस्कार सुनिश्चित किए गए हैं। प्रथम पुरस्कार एसजेवीएन लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा पंजाब नेशनल बैंक को प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार आरईसी, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिला। जबकि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (इंडेन), क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय तथा यूको बैंक को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, खुदरा मंडल, मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, परिमंडल, न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा यूनियन बैंक को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चन्द्र शेखर यादव, कार्यकारी निदेशक (मा.सं.), एसजेवीएन द्वारा राजभाषा गृहपत्रिका 'हिमसंवाद' के चतुर्थ अंक का विमोचन भी किया गया। पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य सदस्य कार्यालयों की सृजनात्मकता तथा रचनात्मक अभिरुचि को बढ़ावा देने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है। इस पत्रिका के प्रकाशन का समस्त दायित्व एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा निभाया गया है। मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक (मा.सं.), चंद्र शेखर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी सदस्य कार्यालय अपने-अपने काल में सहायनीय कार्य कर रहे हैं और आगे भी इसी गति को बनाए रखते हुए अधिकतम कामकाज हिंदी में संपन्न करने का हरसंभव प्रयास करें। इस अवसर पर नराकास के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख एवं एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। **प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टोर डेस्क.**

आरईसी लिमिटेड को एनएसई ईएसजी रेटिंग्स द्वारा वित्तीय संस्थानों में मिली टॉप ईएसजी रेटिंग



नई दिल्ली। आरईसी लि. मिटेड, जो एक प्रमुख एनबीएफसी और बिज. ली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसई, को एनएसई ईएसजी रेटिंग्स द्वारा कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल रेटिंग्स में लीडरशिप पोजीशन हासिल करने की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जिसमें कंपनी ने 80 का शानदार ग्लोबल स्कोर हासिल किया है। यह टॉप रैंकिंग पिछले तीन सालों में कंपनी की अपनी मुख्य गतिविधियों में पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस

सिद्धांतों को शामिल करने की व्यापक और लगातार प्रतिबद्धता को सीधे तौर पर दिखाती है। आरईसी इस सफलता का श्रेय आरईसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मार्गदर्शन में उठाए गए कई रणनीतिक और बुनियादी कदमों को देता है, जिसकी शुरुआत तीन साल पहले अपनी पहली ईएसजी पॉलिसी बनाने से हुई थी।

इस उपलब्धि को हासिल करने वाले मुख्य कामों में ये शामिल हैं:

रणनीतिक योजना और निगरानी: सभी ईएसजी एक्शन पॉइंट्स की सिस्टमैटिक मैपिंग, बेस्ट प्रैक्टिस के साथ बेंचमार्किंग और इंटरनेशनल फोरम जैसे क्लाइमेट डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट (सीडीपी), एसएंडपी सीएसए, एमएससीआई वगैरह के साथ जुड़ाव।

नेट-जीरो पाथवे: आरईसी के लिए नेट-जीरो की दिशा में एक विस्तृत एक्शन प्लान और पाथवे के विकास की दिशा में काम करना।

ऑपरेशनल ईएसजी एक्सीलेंस: आरईसी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 100: ग्रीन पावर और जीरो डिस्चार्ज बिल्डिंग हासिल करना, मेजर ऑफिस फ्लोट को ईवी में बदलना आदि। आरईसी कॉर्पोरेट ऑफिस को गृह 5 रेटेड बिल्डिंग का अवॉर्ड मिला। बेहतर एचआर पॉलिसी और वेल-बीइंग उपाय, जिसमें मानवाधिकार, नैतिकता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एमसीए के एनजी. बीआरबीसी सिद्धांतों पर अनिवार्य ट्रेनिंग शामिल है। बेहतर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) में बेहतर डिस्क्लोजर और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी दूसरी जीआरआई रेफरेंस ईएसजी रिपोर्ट पब्लिश करना।



मजबूत लीडरशिप और कल्चर : पूरे ऑर्गनाइजेशन में एक गहरे ईएसजी कल्चर को बढ़ावा देने में सीनियर मैनेजमेंट का असाधारण और लगातार सपोर्ट।

.जितेंद्र श्रीवास्तव, सीएमडी, आरईसी ने कहा कि यह मील का पत्थर हमारी रणनीतिक दिशा की पुष्टि करता है। हमारी नीतियों की शुरुआत और नेट-जीरो प्लानिंग से लेकर जीआरआई फ्रेमवर्क के तहत हमारे खुलासों को बेहतर बनाने तक। यह उपलब्धि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी पंचामृत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति हमारे पक्के समर्पण को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करती है, यह दिखाती है कि जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाएँ हमारी सफलता का अभिन्न अंग हैं।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टर डेस्क.

शामली के कांधला में खौफनाक तिहरे हत्याकांड ने इंसानियत को कर दिया शर्मसार

आरोपी ने बुर्का न पहनने के कारण पत्नी और दो बेटियों को मार डाला बड़ी बेटी की आंख बाहर निकली मिली



अशोक तिवारी
लखनऊ यूरो प्रमुख

शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक खौफनाक तिहरे हत्याकांड ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोपी पिता फारुक ने कथित इज्जत के नाम पर 10 दिसंबर की रात को अपनी पत्नी ताहिरा और दो मासूम बेटियों आफरीन एवं सहरीन की नृशंस हत्या कर दी। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली, जबकि मौके से खून से सना मोटा डंडा बरामद हुआ है। आशंका है कि उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई। पूछताछ में पता चला कि बिना बुर्के मायके जाने से नाराज था। इसलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने तीनों शवों को

घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक/गहरे गड्ढे में दफना दिया।

एक हफ्ते से लापता थी महिला और उसकी बेटियां

गढ़ी दौलत निवासी फारुक की पत्नी ताहिरा (35) और उसकी दो बेटियां शहरीन (14) व आफरीन (6) करीब एक सप्ताह से लापता थीं। परिजनों द्वारा तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार को ग्राम प्रधान ने थाने पहुंचकर तीनों की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।

पति पर शक, पूछताछ में कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस को सबसे पहले पति फारुक पर शक हुआ। उसे हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म

स्वीकार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर शवों को घर में ही दफना दिया था।

आंगन की खुदाई में मिला खौफनाक सच

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में आंगन की खुदाई कराई गई, जहां से तीनों शव बरामद हुए। शव निकलते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

बुर्का न पहनने से था नाराज

पुलिस और समाचार एजेंसियों के अनुसार, आरोपी फारुक अपनी पत्नी के बिना बुर्का पहने मायके जाने से नाराज था। पूछताछ में उसने बताया कि वह शादी के बाद से पत्नी को पर्दे में रखने पर जोर देता था। उसके मुताबिक, बिना बुर्के बाहर जाने से उसकी सामाजिक इज्जत पर आंच आई, इसी गुस्से में उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

रात में रखी और अंजाम दी साजिश

आरोपी ने कबूल किया कि 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच उसने वारदात को अंजाम दिया। पहले उसने पत्नी को गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर बेटियां जाग गईं, तो बड़ी बेटी को भी गोली मार दी, जबकि छोटी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों शवों को करीब सात फीट गहरे गड्ढे में दफन कर ऊपर से ईंटों का फर्श बिछा दिया।

अवैध हथियार बरामद, सप्लाई नेटवर्क की जांच

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में

इस्तेमाल तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने करीब तीन हजार रुपये में अवैध हथियार खरीदा था। फिलहाल हथियार सप्लायर का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस अवैध हथियार सप्लायर नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

पहले से चल रहा था घरेलू विवाद

मृतका के पिता अमीर ने आरोप लगाया कि फारुक लंबे समय से उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। इसको लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते हर बार बेटी को वापस भेज दिया गया। उनका कहना है कि अगर हालात की गंभीरता का अंदाजा होता तो वे बेटी को कभी ससुराल नहीं भेजते।

भीड़ का आक्रोश और पुलिस का भरोसा

आरोपी को थाने ले जाते समय मायके पक्ष के लोगों ने आक्रोश जताया और उसे पीटने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि शवों को दफनाने में आरोपी को किसी और की मदद तो नहीं मिली।

पंचायतों के बाद भी नहीं बची बेटी

मृतका के पिता अमीर ने बताया कि फारुक आए दिन बेटी को परेशान करता था। इसको लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच दस से अधिक बार पंचायतें हुईं, लेकिन हर बार सामाजिक शर्म के कारण बेटी को वापस भेज दिया गया। अमीर का कहना है कि अगर उन्हें अंदेशा होता तो वह कभी भी बेटी को ससुराल नहीं भेजते।

तीन हजार में खरीदा तमंचा

एसपी ने बताया कि आरोपी ने तीन हजार रुपये में तमंचा खरीदने की बात स्वीकार की है। फिलहाल उसने सप्लायर का नाम नहीं बताया है। पुलिस अवैध हथियार सप्लायर नेटवर्क की भी जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वारदात के खुलासे



के बाद जब पुलिस आरोपी फारुक को थाने ले जा रही थी। इस दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आक्रोशित होकर उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पीटने का प्रयास किया।

निष्पक्ष जांच का भरोसा

पुलिस ने इसके बाद एक्टिव हुई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। मृतका के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आशंका जताई कि इस हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शवों को दफनाने की प्रक्रिया अकेले किसी के बस की बात नहीं है। एसपी ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इन शवों को सेपटी टैंक में दफनाने में ओर किन-किन लोगों ने उसका साथ दिया।

शक के आधार पर पुलिस को दी सूचना

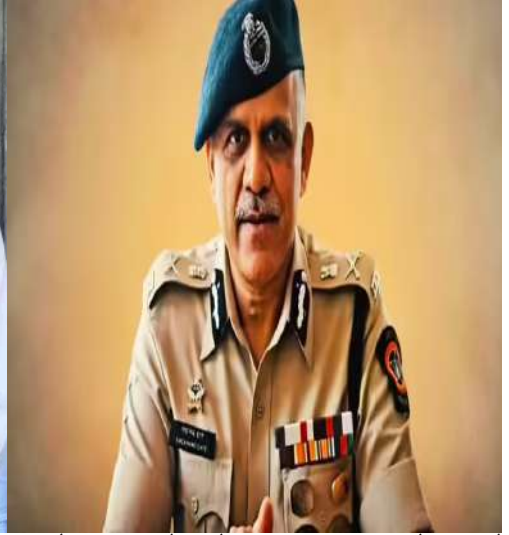
पुलिस के मुताबिक, आरोपी फारुख शादी-विवाह में खाना बनाने का काम करता है। वह अपनी पत्नी ताहिरा (32) और पांच बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसके बच्चों में आफरीन (14), आसमीन (10), सहरीन (7), बिलाल (9) और अरशद (5) शामिल हैं। फारुख का अपने माता-पिता से कई महीनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह अलग मकान में रह रहा था। घटना

के खुलासे से पहले फारुख की पत्नी और दो बेटियां छह दिन से लापता थीं। फारुख के पिता दाउद ने उससे कई बार पत्नी और बेटियों के बारे में पूछा, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। उसने बताया कि उसने उन्हें शामली में किराए के मकान में रखा है। जब दाउद को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने मंगलवार शाम पुलिस को सूचना दी और बेटे पर हत्या का शक जताया।

बुर्का न पहनने पर कत्ल, मानवता के खिलाफ : मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शामली के कस्बा कांथला में बुर्का न पहनने पर हुई महिला और उसके दो बच्चों की हत्या पर कड़ी निंदा की। मौलाना ने कहा कि इस्लाम अपने अनुयायियों को आसानी से अमल करने की इजाजत देता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह भी हुकुम दिया कि महिलाएं अपनी नुमाइश ना करें और पर्दे में रहे। इसी के साथ इस्लाम में महिला के ऊपर जोर जबरदस्ती या दबाव डालने को नहीं कहा गया। महिला के विवेक और जमीर पर छोड़ दिया कि वह अपनी मर्जी और विवेक से लिबास का इस्तेमाल करें। जो घटना जिला शामली के कस्बा कांथला में अंजाम दी गई, वह पूरी इंसानियत का कत्ल है।

आतंकी कसाब को पकड़ने वाले आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी



राजकुमार केशरवानी महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला भारतीय पुलिस सेवा में साढ़े 37 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गईं। विदाई समारोह में शुक्ला को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। वर्ष 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी ने कहा कि यह पद लैंगिक भेदभाव रहित है और काम वही है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। दाते पूर्व में एनआईए के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे और हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र काडर में पुनः नियुक्त किया गया था। दाते (59) ने रश्मि शुक्ला से 3 जनवरी को राज्य पुलिस मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। दो लाख से अधिक कर्मियों वाले महाराष्ट्र पुलिस बल के प्रमुख के रूप में दाते का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

वसंत दाते ने अजमल कसाब को पकड़ने में निभाई थी अहम भूमिका
महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को 26/11 हमले के दौरान उनकी

बहादुरी के लिए याद किया जाता है। आतंकी हमले के दौरान उनकी वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। दाते ने अजमल कसाब और उसके लश्कर-ए-ताइबा के सहयोगी अबू इस्माइल से संघर्ष किया, उन्हें चोटें आईं और जब तक वह बेहोश नहीं हो गए, तब तक उन्होंने उन्हें रोके रखा। उनकी सूझबूझ के कारण ही कसाब जिंदा पकड़ा गया। उस समय वे मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे। 26 नवंबर, 2008 की उस भयावह रात को मध्य क्षेत्र के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दाते को एक फोन आया कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) के पास आतंकी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही 10 आतंकी एक नाव के जरिये मुंबई में घुस आए थे और शहर में फैल गए थे। इस हमले में मुंबई पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे और अशोक कामटे सहित 18 बहादुर बलिदान हुए। आतंकियों के फेंके गए ग्रेनेड के हमले में दाते गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज भी उनके शरीर में ग्रेनेड के धातु के टुकड़े फंसे हुए हैं, जिसमें एक उनकी आंख के पास भी है और वह इन स्थायी निशानों को चोटों के रूप में नहीं, बल्कि

युद्ध क्षेत्र से लाए गए पदक के रूप में देखते हैं। जब तक दाते और उनकी टीम सीएसटी पहुंची, तब तक दोनों आतंकी कसाब और इस्माइल वहां से चले गए थे और पास के कामा अस्पताल की छत पर कब्जा कर लिया था। टीम ने उनका वहां तक पीछा किया। उन्हें पता था कि दो लोग वहां हैं, लेकिन उन्हें आतंकियों के पास मौजूद हथियारों और गोला-बारूद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल, दाते के नेतृत्व वाली टीम ने दोनों से मुकाबला करने का फैसला किया। टीम की त्वरित प्रतिक्रिया और निर्णायक कार्रवाइयों ने अस्पताल में मरीजों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनके स्थान के बारे में सूचित करने के अलावा दोनों आतंकियों पर गोलीबारी जारी रखी।

महत्वपूर्ण पदों पर किया काम

एनआईए में शामिल होने से पहले, सदानंद दाते महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें मीरा भायंदर वसई विरार के



पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था के संयुक्त आयुक्त और मुंबई में अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त शामिल हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में उप महानिरीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में महानिरीक्षक के रूप में दो कार्यकाल भी पूरे किए हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए भयावह हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों से निपटने में उनकी भूमिका के लिए दाते को 2008 में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2007 में राष्ट्रपति पुलिस मेधावी सेवा पदक और 2014 में राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है।

15 साल की उम्र में पिता का निधन

सदानंद दाते का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पिता सदानंद को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। मेहनत मजदूरी करके पर परिवार चलाते और सदानंद दाते को स्कूल भेजते। लेकिन सदानंद दाते जब 15 साल के थे तब उनके पिता वसंत का अचानक निधन हो गया। परिवार पर गाज गिर पड़ी।

मां ने घरों में किया काम, सदानंद ने बाँटे अखबार

सदानंद की मां ने घर चलाने के लिए

घरों में काम करना शुरू किया। वह सुबह से देर रात तक घरों में झाड़ू-पाँछा करतीं, जूटे बर्तन साफ करतीं ले। कन परिवार के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। सदानंद ने मां का हाथ बंटाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने का काम शुरू किया। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या वह बीमार हों सुबह उठकर वह घरों में अखबार डालते। उसके बाद स्कूल पढ़ने जाते। तमाम संघर्ष थे लेकिन सदानंद ने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब भी समय मिलता, सदानंद दाते पढ़ने बैठ जाते।

सदानंद दाते कैसे बने आईपीएस

सदानंद दाते ने स्थानीय सरकारी स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सदानंद ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने 1990 में आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। इस दौरान उन्होंने हमफ्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत मिनेसोटा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉइट कॉलर और संगठित अपराध को नियंत्रित करने के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन किया। भारत लौटने पर उन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) के पद पर तैनात किया

गया।

सदानंद दाते ने ऐसा क्या किया कि बने हीरो

मुंबई हमले के दौरान सदानंद दाते सेंट्रल रीजन के एसीपी थे। मुंबई हमले के दौरान वह अपने साथियों के साथ फ्रंटलाइन पर उतरे। आतंकवादियों का डटकर सामना किया। वह सीधे उस कामा अस्पताल की बिल्डिंग में घुस गए, जहां से आतंकी उनकी पुलिस टीम पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान वह ग्रेनेड की चपेट में आ गए। यह ग्रेनेड उनसे तीन फुट की दूरी पर फटा था। इस हमले में सब इंस्पेक्टर प्रकाश मोरे की मौत हो गई। सदानंद दाते घायल हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हा. री। वह आतंकियों से बराबर भिड़े रहे। वह अपनी टीम के साथ घायल अवस्था में ही अस्पताल की छठवीं मंजिल तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ सीढ़ियों के पास छिपकर आतंकियों की फायरिंग का जवाब देना शुरू कर दिया। लगभग 40 मिनट तक फायरिंग होती रही। आतंकियों ने सदानंद दाते की तरफ ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेट फटा और सदानंद बुरी तरह घायल हो गए। इसी दौरान अजमल कसाब और इस्माइल मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। हालांकि सदानंद दाते और उनकी टीम ने अस्पताल को बड़े हमले से बचा लिया।

मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया : खरगे

कांग्रेस कार्यसमिति बैठक : मल्लिकार्जुन खरगे ने की कई मुद्दों पर हुई चर्चा, पार्टी को दिया संदेश



डॉ. ईशा सलाहकार संपादक

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' बनाए जाने को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर 'गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने' का आरोप लगाया और कहा कि इस विषय पर राष्ट्रव्यापी जनान्दोलन खड़ा करना होगा। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की और कहा कि इससे पूरा भारत चिंतित है। खरगे ने कांग्रेस नेताओं से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान किया और यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश है तथा

ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस के मतदाताओं के नाम न काटे जाएं बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केंसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, लो. कसभा सदस्य शशि थरूर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। खरगे ने बैठक में कहा कि हम आज ऐसे मौके पर विचार और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी

सरकार ने छुरा घोंपा है। मोदी सरकार ने काम के अधिकार पर सुनियोजित और क्रूर हमला किया है। शर खरगे ने कहा कि मोदी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे की ही चिंता है। उनका कहना था कि मनरेगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का ऐसा दूरदर्शी कदम था, जिसे पूरे विश्व ने सराहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना। इससे पलायन रुका, गांवों को अकाल, भूख, और शोषण से मुक्ति मिली। इस योजना ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को भरोसा दिया कि गरीबी से जंग में सरकार उनके साथ खड़ी है। शर खरगे ने दावा किया कि मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन या मूल्यांकन के, राज्यों से या राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा के



जताया कि जैसे किसानों के आंदोलन से सरकार झुकी थी, वैसे ही इस बार भी जनता की ताकत रंग लाएगी। बैठक में संगठन सृजन अभियान, 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ED, CBI, IT के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई। दिग्विजय सिंह ने संगठन में विकेंद्रीकरण की जरूरत बताई। कुल मिलाकर CWC बैठक से कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पार्टी आने वाले समय में वैचारिक और जन आंदोलन की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

खरगे ने देशव्यापी आंदोलन की जरूरत पर दिया जोर

खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। इसका पुरजोर विरोध देश के हर का. ने में होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार ने कॉरपोरेट हितों में भूमि अधिग्रहण कानून बदला तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम किसानों के हक में डटे रहे और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री को किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानून वापस लेने पड़े। इन काले कानूनों की वापसी की भविष्यवाणी राहुल जी ने बहुत पहले कर दी थी और हाल में उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार को दुबारा मनरेगा बहाल करना होगा। उनके मुताबिक, पिछले 76 वर्षों में संविधान ने देश के नागरिकों को इतना सिखा दिया है कि कोई तानाशाह उनका अधिकार छीन नहीं सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मनरेगा पर ठोस योजना बनाएं, राष्ट्रव्यापी, जन-आंदोलन खड़ा करें। यह लड़ाई हम जीतेंगे। इस कठिन हालत में देश भर के कमजोर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक देश के करीब 500 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा अगले 120 दिनों में शेष जिलों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि बात

बिना इसे खत्म करके नया कानून थोप दिया। उन्होंने कहा कि यह सारा काम तीन काले कृषि कानूनों की भांति किया गया। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का संकेत देते हुए संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर जोर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति (सीड. ब्ल्यूसी) की अहम बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश इस समय एक गंभीर दौर से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, संविधान की भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है और आम नागरिकों के अधिकार लगातार सीमित होते जा रहे हैं। खरगे ने साफ कहा कि यह केवल हालात पर चर्चा करने का समय नहीं, बल्कि आने वाले बड़े संघर्ष की दिशा तय करने का निर्णायक मोड़ है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सोनिया गांधी के हालिया लेख का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा ने गांधी जी के सर्वोदय के सपने को हकीकत में बदला था। यह योजना सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा का कमजोर होना सामाजिक और आर्थिक रूप से देश के लिए घातक साबित होगा। खरगे ने याद दिलाया कि काम करने का अधिकार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की आत्मा है, जिसे यूपीए

सरकार ने शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार के रूप में मजबूत किया था। खरगे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियां आम जनता के लिए नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों के हित में बनाई जा रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के उस विचार को दोहराया, जिसमें विशेषाधिकार और एकाधिकार का विरोध किया गया था। उनका कहना था कि जो व्यवस्था समाज के साथ साझा नहीं हो सकती, वह नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। अपने श्रम मंत्री कार्यकाल को याद करते हुए खरगे ने कहा कि मनरेगा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई थी। उन्होंने बताया कि 2006 में आंध्र प्रदेश के एक गांव से सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना बनी, जिसने ग्रामीण भारत को सहारा दिया, पलायन रोका और दलितों, आदिवासियों, महिलाओं व भूमिहीन मजदूरों को सुरक्षा दी। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना गंभीर अध्ययन और राज्यों व विपक्ष से चर्चा किए मनरेगा को खत्म कर नया कानून लागू किया। उन्होंने इसकी तुलना कृषि कानूनों से की, जिन्हें बाद में जनता के दबाव में वापस लेना पड़ा। खरगे ने ऐलान किया कि मनरेगा को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने विश्वास



केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। हमें प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय, जवाबदेह और लड़ाकू बनाना होगा। उन्होंने अगले साल अप्रैल-मई 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी तैयारियां जारी हैं। हम संगठित हो कर, पूरी एकता से चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को ताकतवर बनाएंगे। खरगे ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआ.ईआर) के विषय पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक साजीश है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार तथ्यों और उदाहरणों के साथ 'वोट चोरी' का प्रमाण देश के सामने रखा है। भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत जगज्जिहिर है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मतदाताओं के नाम न काटे जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि हमें देखना होगा कि मतदाता सूची से गरीब और कमजोर तबकों के लोगों के खास तौर पर दलित, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के नाम न कटने पाएं। उन्होंने कहा कि 2027 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां भी अभी से एकजुट होकर मतदाता सूचियों से लेकर सभी तैयारी में लग जाना चाहिए। खरगे ने जांच

एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा और संघ परिवार 'नेशनल हेराल्ड' के मुद्दे पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की छवि को खराब करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। 'सत्यमेव जयते' ये बात राहुल हमेशा कहते हैं, हमारी जीत होगी। बांग्लादेश की स्थिति पर उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने पूरे देश को चिंतित किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि दो दिन पहले क्रिसमस के मौके पर कई इलाकों में भाजपा, आरएसएस और इनसे संबंधित संगठन के लोगों ने भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। इससे दुनिया के सामने हमारी छवि धूमिल हुई है।

भाजपा की 'संगठन शक्ति' की तारीफ, संगठन में विकेंद्रीकरण पर जोर दिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक से पहले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की "संगठन शक्ति" की तारीफ कर अपने दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। हालांकि, उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि वह आरएसएस तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी हैं, और उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ

की है। सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय ने कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पार्टी संगठन में विकेंद्रीकरण की पैरवी की। कार्य समिति की बैठक शुरू हो 'ने' से पहले दिग्विजय सिंह ने 'एक्स' पर एक पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हुए हैं तथा उनके पीछे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। सिंह ने पोस्ट किया, "कोरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सियाराम।" शिवावाद खड़ा होने पर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी था, घोर विरोधी हूँ और रहूंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कार्य समिति की बैठक में विकेंद्रीकरण की पैरवी की है, सिंह ने कहा कि मुझे जो कहना था, वो मैंने बैठक के दौरान कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि क्या संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना, क्या बुरी बात है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मेरे कार्यकाल को देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने विकेंद्रीकृत तरीके से काम किया। यह मेरा विचार है।

पीएम ने मनरेगा खत्म करने का फैसला कैबिनेट और चौहान से बिना पूछे किया: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया और ऐसा करते समय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा कैबिनेट से विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई



कि सरकार के इस कदम के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होगा। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। मनरेगा पंचायती राज में सीधा राजनीतिक हिस्सा, 'दारी और वित्तीय सहयोग का साधन था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अधिकारों के विचार और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्यों से पैसा छीन रही है। यह सत्ता और वित्तीय व्यवस्था का केन्द्रीकरण है। इससे देश और गरीब जनता को नुकसान है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मनरेगा को खत्म करने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया गया है और मंत्री (चौहान), कैबिनेट से बिना पूछे यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले यह फैसला किया है। उनका कहना था, "इससे पता चलता है कि देश में 'वन मैन शो' चल रहा है। नरेन्द्र मोदी जो करना चाहते हैं, करते हैं, जिसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है। आप देखना नरेन्द्र मोदी ने जो फैसला लिया है, वह तबाह हो जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम इसका विरोध

करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा विपक्ष सरकार के इस कदम के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होगा। संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच बीते 18 दिसंबर को 'विकसित भारत— जी राम जी विधेयक, 2025' को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संतुति के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा।

आरएसएस की तारीफ करने को लेकर राहुलगांधीनेदिग्विजयसिंहपरकसातंज!

कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन के भीतर एक दिलचस्प वाक्या देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद चाय-नाश्ते के दौरान आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस को आरएसएसदृष्टीबीजपी के संगठनात्मक ढांचे से सीखने वाले बयान के बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का आमनादृशामना हुआ। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसी बातचीत के दौरान पीछे खड़े एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। फिर राहुल गांधी ने हंसते हुए प्रतिक्रिया

दी, बिल्कुल सही कहा कि दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। सूत्र बताते हैं कि यह पूरी बातचीत सहज माहौल में हुई। चाय-नाश्ते के इस अनौपचारिक कार्यक्रम में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद थे। इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मुस्कराते हुए दिग्विजय सिंह को एक नसीहत भी दे डाली। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने हंसते हुए तंज के माध्यम से कह दिया कि जो भी बात रखनी हो, वह पार्टी के आंतरिक मंचों पर रखी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मुद्दे हल नहीं होते। दरअसल पूरा मामला सोशल मीडिया पर की गई दिग्विजय सिंह की पोस्ट से जुड़ा है। इसमें उन्होंने आरएसएस के संगठनात्मक शक्ति का जिक्र करते हुए तारीफ की है। उनके इसी बयान पर पार्टी के अंदर विरोध और समर्थन देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह ने 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता एलके आडवाणी के पास जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'शजो लोग कभी जमीनी स्तर पर काम करते थे, वे संगठनात्मक पदानुक्रम में ऊपर उठकर मुख्यमंत्री और आखिरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की शक्ति बताया था। उन्होंने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं को टैग किया था।

दिग्विजय सिंह ने दी सफाई

विवाद में घिराने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बातों को गलत समझा गया। मैं संगठन का समर्थन करता हूँ। मैं आरएसएस और मोदी जी के खिलाफ हूँ। आपने गलत समझा है। मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस और मोदी का कट्टर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। क्या संगठन को मजबूत करना और उसकी तारीफ करना बुरी बात है।

भारत एक अस्थिर विश्व में: 2025 की भू-राजनैतिक समीक्षा



विकास पारिक विदेश प्रतिनिधि (लंदन)

वर्ष 2025 विश्व व्यवस्था के गहन और त्वरित पुनर्गठन का वर्ष साबित हुआ है, जहां शीत युद्ध के बाद का दौर बिखरा पड़ा है और एक बहुरूपीय होड़ नई सामान्य स्थिति को परिभाषित करती है। एक उभरते भारत के लिए, बाहरी अस्थिरता का यह दौर केवल प्रबंधित की जाने वाली चुनौती नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपने सांस्कृतिक वजन और रणनीतिक स्वायत्तता को स्थापित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर नेतृत्व में, भारत की विदेश नीति निपुण, हित-संचालित व्यावहारिकता द्वारा चित्रित की गई है — जहां लाभकारी हो वहां साझेदारी बनाना और जहां सिद्धांत दांव पर हों वहां दृढ़ता से खड़े रहना। निम्नलिखित विश्लेषण 2025 के दस प्रमुख बाहरी भू-राजनैतिक विकासों का विवरण देता है जिन्होंने सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और आर्थिक गति को आकार दिया है, यह दर्शाते हुए कि भारत अब विश्व घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील

नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उनके परिणामों को रूप दे रहा है।

1-इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) का अंतिम रूप लेना

पूरे 2025 के दौरान, महत्वाकांक्षी IMEC परियोजना, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, स्मरण पत्र से मूर्त समझौतों की ओर बढ़ी, क्षेत्रीय हिचकिंच। ाहट पर काबू पाते हुए। यह बाहरी विक।।स चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (उत्) के लिए एक स्मारकीय रणनीतिक प्रतिवाद है, जो भारत से यूएई, सऊदी अरब और इजराइल होते हुए यूरोप तक एक डिजिटल और हरित-ऊर्जा से जुड़ा गलियारा प्रस्तावित करता है। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका की वित्तपोषण और राजनीतिक स्वीकृति सुरक्षित करने में सक्रिय भागीदारी ने आर्थिक एकीकरण के एक नए अक्ष का सृजन किया है। भारत के लिए, यह ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित करता है, इसके प्रौद्योगिकी और हरित उद्योगों के लिए निर्यात क्षमता को बढ़ाता है, और यूरेशिया-व्यापी नेटवर्क के एक अनिवार्य

इंडो-पैसिफिक एंकर के रूप में इसकी भूमिका को गहरा करता है, जिससे विवादित पूर्वी समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम होती है।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत को अब अथक अवसंरचना कूटनीति के साथ परियोजना के पूर्वी हिस्से को आगे बढ़ाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह यूरेशियाई व्यापार के लिए प्राथमिक मार्ग बन जाए, जो दशकों तक रोजगार और रणनीतिक लाभ उत्पन्न करे।

2- दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ना और आसियान का पुनर्गठन

2025 में, फिलीपींस की आपूर्ति मिशन के खिलाफ चीन के निरंतर दबाव और पुनर्ग्रहित चट्टानों के नए सैन्यीकरण ने महत्वपूर्ण सीमाएं पार कर लीं। इस बाहरी आक्रामकता ने आसियान के भीतर एक निश्चित कठोरता को ट्रिगर किया है, जिसमें वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख सदस्यों ने अमेरिका, जापान और महत्वपूर्ण रूप से, भारत के साथ रक्षा संबंधों को काफी गहरा किया है। एक विश्वसनीय संतुलनकारी साझेदार की क्षेत्र की खोज भारत की

‘एक्ट ईस्ट’ नीति के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जो अब पूरे जोर पर है। भारत ने नौसेना तैनाती बढ़ाकर, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की त्वरित डिलीवरी, और अमेरिका व आसियान नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय अभ्यासों के साथ जवाब दिया है, जिससे वह दक्षिणपूर्व एशिया में एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित हो रहा है।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत रसद समझौतों और खुफिया साझेदारी के माध्यम से इन साझेदारियों को संस्थागत रूप देगा, अपने पूर्वी नौसेना कमान को क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के केंद्र में बदल देगा, जो सीधे तौर पर चीनी दखलंदाजी पर अंकुश लगाएगा।

3-यूके-रवांडा शरणार्थी समझौता और वैश्विक प्रवासन संकट

2025 में यूके-रवांडा शरणार्थी समझौते ने प्रवासियों के अपतटीय प्रसंस्करण के लिए एक स्पष्ट वैश्विक मिसाल कायम की। इसके साथ ही, सूडान और साहेल में बिगड़ते संघर्ष और कई देशों में आर्थिक पतन ने यूरोप और अरब सागर की ओर प्रवासन की नई लहरें पैदा कर दीं। इन बाहरी संकटों ने पूर्वी सीमा पर पार-सीमा घुसपैठ के प्रयासों को बढ़ा कर, संसाधनों पर दबाव डालकर और साझेदार राष्ट्रों के साथ जटिल कूटनीतिक चुनौतियां पैदा करके सीधे भारत को प्रभावित किया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बाड़ के निर्माण को गति देकर, तटीय निगरानी नेटवर्क को मजबूत करके, और मूल कारणों से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करके जवाब दिया है।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत अस्थिर क्षेत्रों में सीधे स्रोत जुड़ाव और क्षमता निर्माण के एक मॉडल का प्रचार करेगा, जिससे वह प्रवासन संकटों का समाधान बनेगा, न कि केवल एक पारगमन क्षेत्र, साथ ही उन्नत तकनीक से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेगा।

4-अफ्रीकी लिथियम कार्टेल का गठन

ओपेक के मॉडल के बाद, प्रमुख अफ्रीकी लिथियम उत्पादकों/विशेष रूप

से जिम्बाब्वे, नामीबिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगोकुने 2025 की शुरुआत में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने और स्थानीय प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन की मांग के लिए एक उत्पादक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया। वैश्विक बैटरी आपूर्ति श्रृंखला पर इस बाहरी आघात ने भारत की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण योजनाओं को सीधे खतरे में डाल दिया। भारत की सक्रिय प्रतिक्रिया एक कूटनीतिक और निवेश धमाका रही है, जिसने इन देशों में खानिज भारत विदेश लिमिटेड जैसे कंसोर्टियम के माध्यम से दीर्घकालिक खरीद समझौते सुरक्षित किए और संयुक्त उद्यम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए। यह कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और साथ ही दक्षिण-दक्षिण आर्थिक साझेदारी का निर्माण करता है। भविष्य की ओर देखते हुए भारत इसका लाभ उठाकर खदान से बाज. 17 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करेगा, चीन द्वारा नियंत्रित रिफाइनिंग पर निर्भरता कम करेगा और हरित प्रौद्योगिकी विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करेगा।

5- यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का पूर्ण क्रियान्वयन

2025 में यूरोपीय संघ के CBAM का पूर्ण, आक्रामक प्रवर्तन, जो स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे कार्बन-गहन आयातों पर कर लगाता है, भारतीय निर्यातकों के लिए एक गंभीर बाहरी आर्थिक झटका बना है। एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार से यह “हरित संरक्षणवाद” एक त्वरित, संरचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। भारत सरकार ने अपने स्वयं के कार्बन व्यापार योजना को तेज किया, प्रमुख उद्योगों के लिए हरित ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य किया और पया. प्त उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहनों के साथ एक “ग्रीन स्टील इनिशिएटिव” शुरू किया। हालांकि शुरुआत में यह एक

चुनौती थी, इसने भारत के मुख्य उद्योगों के आवश्यक आधुनिकीकरण को उत्प्रेरित किया है, जिससे दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत अब अपने कम-कार्बन वाले औद्योगिक उत्प. 17 को “मेड इन ग्रीन इंडिया” बैनर के तहत आक्रामक रूप से बाजार में उतारेगा, अनुपालन को एक ब्रांड लाभ में बदल देगा और अपने कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र की पारस्परिक मान्यता के लिए बातचीत करेगा।

6- बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता

2024 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश में हिंसक घटनाक्रम और राजनीतिक उथल-पुथल निर्णायक रूप से 2025 में आ गई, जिससे भारत के लिए एक अस्थिर और अनिश्चित पूर्वी सीमा बन गई है। यह बाहरी अस्थिरता सीमा पार सुरक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण लाभों को उलटने का जोखिम पैदा करती है, भारत-विरोधी उग्रवादी समूहों के लिए सुरक्षित ठिकानों को फिर से खोलने की धमकी देती है और अप्रत्याशित शरणार्थी प्रवाह को ट्रिगर करती है। भारत ने एक नाजुक, फिर भी दृढ़, द्वि-पक्षी नीति अपनाई है, सभी राजनीतिक खिलाड़ियों के साथ खुले चैनल बनाए रखना, साथ ही सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और यह स्पष्ट संकेत देना कि सुरक्षा मोर्चे पर कोई भी पिछड़ा. पन या चीन की ओर झुकाव के तत्काल और दूरगामी परिणाम होंगे।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत आर्थिक प्रोत्साहन और सुरक्षा आश्वासनों के माध्यम से स्थिति को स्थिर करने का प्रयास करेगा, लेकिन साथ ही सीमा को सील करने और भारत समर्थक तत्वों का समर्थन करने के लिए मजबूत आकस्मिक योजनाएं तैयार करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके रणनीतिक हित पड़ोसी अराजकता से सुरक्षित रहें।

7- लाल सागर संकट (चल रहा)

लाल सागर में व्यावसायिक शिपिंग पर हौथी हमले, ईरानी समर्थन के साथ 2025 में जारी रहे, ने वैश्विक व्यापार की एक महत्वपूर्ण धमनी को गंभीर रूप से

बाधित किया है। इस बाहरी सुरक्षा संकट ने भारतीय निर्यात और ऊर्जा आयात के लिए शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। भारत की प्रतिक्रिया विशिष्ट रूप से मजबूत और स्वतंत्र रही है। रक्षा क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक युद्धपोतों की एक शक्तिशाली बेड़े की तैनाती, सभी राष्ट्रों के लिए स्वतंत्र रूप से समुद्री मार्गों की सुरक्षा, और अमेरिका के नेतृत्व वाले “समृद्धि संरक्षक” गठबंधन में शामिल होने से इनकार। यह भारत की एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में क्षमता का प्रदर्शन करता है और कूटनीतिक स्वायत्तता को त्यागे बिना अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है।¹⁵ भविष्य की ओर देखते हुए भारत इस परिचालन उपस्थिति का उपयोग खाड़ी अरब देशों के साथ नौसैनिक साझेदारी को गहरा करने और दीर्घकालिक ठिकाना पहुंच सुरक्षित करने के लिए करेगा, पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी शक्ति प्रक्षेपण को स्थायी रूप से बढ़ाएगा।

8- मेक्सिको में “नियरशोरिंग” उछाल और अमेरिकी व्यापार विविधीकरण

2025 में एशिया पर निर्भरता कम करने की रणनीति के रूप में अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं का मेक्सिको की ओर त्वरित स्थानांतरण कृषि निर्यात शोरिंग एक जटिल बाहरी आर्थिक चुनौती प्रस्तुत करता है। यह भारत से कुछ विनिर्माण निवेश को मोड़ता है और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। भारत ने यूके और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (म्हज) के साथ अपने व्यापार समझौता वार्ताओं में तेजी लाकर, और पैमाने, कुशल श्रम और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के अपने अनूठे संयोजन का आकर्षक विपणन करके प्रतिवाद किया है। ध्यान सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो गया है जहां मेक्सिको सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत महत्वपूर्ण पश्चिमी साझेदारों के साथ षष्ठ-तटीयकरण समझौतों को सुरक्षित करने पर दोगुना जोर देगा, स्वयं को कम लागत वाले विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए

रणनीतिक, लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में स्थापित करेगा।

9- पाकिस्तान में रणनीतिक अराजकता

2025 में पाकिस्तान का गहरे आर्थिक निराशा और राजनीतिक-सैन्य दुष्क्रियाशीलता में उतरना एक महत्वपूर्ण बाहरी कारक है। राज्य के कगार पर होने और उसका ध्यान आंतरिक आग में खप जाने से, सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने की उसकी क्षमता कमजोर हुई है, लेकिन एक हताश, विचलित करने वाले सैन्य दुस्साहस का जोखिम बढ़ गया है। भारत ने इस अस्थिर परिदृश्य का सामना अभेद्य रक्षात्मक शक्ति और कूटनीतिक अलगाव के रुख के साथ किया है। पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य तत्परता चरम पर है, जबकि भारत आतंक वित्तपोषण पर पाकिस्तान को वैश्विक ग्रे सूची में डालने के प्रयासों का नेतृत्व करता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर भारत की स्थिति को क्षेत्र की एकमात्र स्थिर शक्ति के रूप में मजबूत करता है।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत एक कठोर निवारक बनाए रखेगा, साथ ही संभावित राज्य पतन परिदृश्यों के लिए तैयारी करेगा, जिसमें इसके परमाणु संसाधनों की सुरक्षा और अतिप्रवाह को रोकना शामिल है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता के गारंटर के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि होगी।

10- कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्वांटम कंप्यूटिंग में सफलता

2025 में अमेरिका के नेतृत्व वाले एक प्रौद्योगिकी कंसोर्टियम द्वारा स्थिर, त्रुटि-सुधारित क्वांटम कंप्यूटिंग में पुष्ट, सहकर्मी-समीक्षित सफलता ने एक वैश्विक तकनीकी-सुरक्षा दौड़ को ट्रिगर किया है। इस बाहरी तकनीकी छलांग से वर्तमान एन्क्रिप्शन अप्रचलित होने का खतरा है, जो भारत के डिजिटल अवसर संरचना, वित्तीय प्रणालियों और राष्ट्रीय सुरक्षा संचार के लिए एक मौलिक जोखिम पैदा करता है। भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और रणनीतिक रही है।

अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में बड़े पैमाने पर राज्य-समर्थित निवेश, एक क्वांटम-हाइब्रिड सुपरकंप्यूटिंग सुविधा

की स्थापना, और यह सुनिश्चित करने के लिए जापान और फ्रांस के साथ एक नया महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदारी का निर्माण कि यह इस क्रांति के अग्रिम पंक्ति में रहे, न कि इसका शिकार बने।

भविष्य की ओर देखते हुए भारत का लक्ष्य संप्रभु क्वांटम-प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन विकसित करना और फार्मास्यूटिकल्स और सामग्री विज्ञान के लिए क्वांटम अनुप्रयोगों में एक विशेषज्ञता स्थापित करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाला युग भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करे, न कि खतरे में डाले।

निष्कर्ष: संकट की आग में एक विश्वगुरु का निर्माण

2025 की घटनाओं ने भारत को अचानक नहीं पकड़ाया उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र को प्रकट किया जो रणनीतिक दूरदर्शिता और अटूट संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। जहां बाहरी झटके कभी शर्तें तय करते थे, वहां भारत अब उन्हें तय करता है। अपनी ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के भविष्य को सुरक्षित करने से लेकर समुद्री मार्गों की रक्षा और नए आर्थिक गलियारों को आकार देने तक, मोदी सरकार ने दिखाया है कि एक मजबूत, सांस्कृतिक रूप से आश्वस्त भारत विश्व का अनिवार्य स्थिरीकरणकर्ता है। पड़ोसियों से उत्पन्न अराजकता और दूर के गुटों के संरक्षणवाद का सामना शिकार से नहीं, बल्कि गणनापूर्ण कार्रवाई और आत्मनिर्भर नवाचार से किया जाता है। जैसे-जैसे विश्व एक संकट से दूसरे संकट की ओर डगमगाता है, भारत दृढ़ खड़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, और नेतृत्व कर रहा है। संदेश स्पष्ट है। 21वीं सदी उन लोगों द्वारा आकार नहीं दी जाएगी जो शक्ति विरासत में पाते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा आकार दी जाएगी, जैसे भारत, जिनके पास सांस्कृतिक सहनशक्ति और राजनीतिक इच्छाशक्ति है इसे अर्जित करने की। भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जिसकी भारत प्रतीक्षा करता है। यह कुछ ऐसा है जिसका भारत निर्माण करता है, एक स्वतंत्र निर्णय के साथ।

ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है 2026 की राह

दंगे, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था के पतन के सहारे सत्ता पर कब्जा के लिए चौतरफा घेराबंदी कर रही भाजपा



नरेश कुमार श्रीवास्तव
पश्चिम बंगाल ब्यूरो प्रभारी

कोलकाता। वर्ष 2011 में सत्ता में आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब तक की सबसे कठिन चुनावी चुनौतियों में से एक का सामना कर रही है। वर्ष 2025 में सामने आए कई सामाजिक-राजनीतिक घटनाक्रमों ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है। राज्य में लगातार हुए दंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था सहित कानून व्यवस्था की अन्य बदहाली ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा आम लोगों में फैलाया है। इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कब्जा करने के लिए चौतरफा घेराबंदी की रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है।

तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप, व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, लगातार कानूनी झटके और राज्य की नाजुक वित्तीय स्थिति ये सभी ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जो आगामी चुनावों से पहले टीएमसी के लिए बड़ी परेशानी बनते दिख रहे हैं।

वर्ष 2025 के कई ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके चलते 2026 का विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस के लिए 2011 के बाद सबसे कठिन माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2011 में ही 34 वर्षों के वाम मोर्चा शासन का अंत हुआ था और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी।

मुर्शिदाबाद दंगे और राजनीतिक असर

अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक-बहुल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध के दौरान हिंसक दंगे भड़क उठे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपट्टी ने टिप्पणी की कि यदि राज्य सरकार समय रहते ठोस कदम उठाती, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र

बलों की तैनाती पर निर्णय भी शामिल था, तो स्थिति इतनी हिंसक नहीं होती।

इसके बाद 23 दिसंबर को मुर्शिदाबाद की एक जिला अदालत ने दंगों से जुड़े मामले में 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बताए गए। भाजपा ने इस फैसले के आधार पर आरोप लगाया कि राज्य पुलिस ने सत्तारूढ़ दल से नजदीकी के कारण दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आरोप का जवाब देना टीएमसी के लिए आसान नहीं होगा।

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर यू-टर्न

2025 के शुरुआती महीनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा था कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम को पश्चिम बंगाल में किसी भी स्वरूप में लागू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वर्ष के दूसरे हिस्से में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बेहद कम समयसीमा के भीतर 'उमीद पोर्टल' पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के निर्देश दिए।

इससे वाम मोर्चा, कांग्रेस और ऑल इंडिया से. क्युलर फ्रंट समेत गैर-भाजपा विपक्षी दलों को टीएमसी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाने का मौका मिला। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जहां मुर्शिदाबाद दंगों ने हिंदू मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को नाराज किया, वहीं वक्फ संपत्ति पंजीकरण पर पलटवार ने मुस्लिम मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को भी असंतुष्ट कर दिया।

नौकरियों की हड़िकरण का मामला

अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की और

कहा कि राज्य सरकार 'दागी' और 'निर्दोष' अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची देने में विफल रही, इसलिए पूरे पैनल को रद्द करना पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन वह अब भी कानूनी अड़चनों में फंसी हुई है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं कि टीएमसी शासन में निष्पक्ष भर्ती की कल्पना ही बेमानी है।

आर.जी. कर दुष्कर्म-हत्या मामला

अगस्त 2024 में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला 2025 में भी तृणमूल कांग्रेस के लिए सियासी सिरदर्द बना रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में सुनवाई जारी है। जनता के बीच यह धारणा बनी रही कि राज्य प्रशासन के प्रभावशाली वर्गों ने मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश की। इसके अलावा, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जूनियर डॉक्टरों के तबादलों को लेकर टीएमसी पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के आरोप भी लगे।

कसबा लॉ कॉलेज गैंगरेप मामला

2025 में कोलकाता के कसबा स्थित एक लॉ कॉलेज परिसर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने भी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दीं। इस मामले में तीनों आरोपी तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) से जुड़े पाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षण संस्थान राजनीतिक संरक्षण प्राप्त असामाजिक तत्वों के अड्डे बनते जा रहे हैं।

महंगाई भत्ता बकाया और अवमानना

राज्य सरकार के सामने एक और कानूनी संकट तब खड़ा हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने जून 30 तक राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के 25 प्रतिशत बकाया भुगतान का निर्देश दिया। आदेश का पालन न होने पर सरकार पर अवमानना की तलवार लटकने लगी है।

हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अवमानना की कार्रवाई से राहत मिलना सुनिश्चित नहीं है। इन तमाम घटनाक्रमों के चलते राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वर्ष 2026 का विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित हो सकता है।

बचकर रहें ठंड में लकवा की बीमारी से



लिए आशाजनक मार्ग की खोज करता है जिसे अब कई व्यक्ति अपना सकते हैं। आइए इस स्थिति को समझने से शुरुआत करें।

लकवा कई कारणों से हो सकता है

स्ट्रोक: स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति बाधित या कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते। कुछ ही मिनटों में, मस्तिष्क की कोशिकाएँ मरने लगती हैं, जिससे लकवा हो सकता है, आमतौर पर शरीर के एक तरफ।

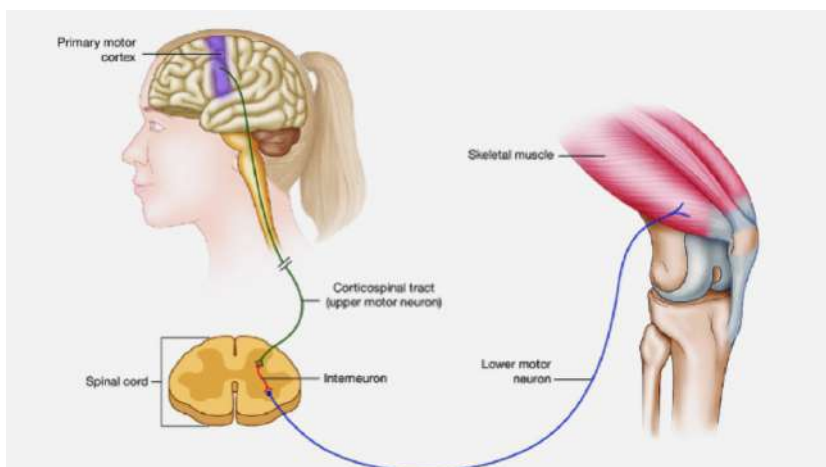
सिर या रीढ़ की हड्डी में चोट: सिर या रीढ़ की हड्डी में दर्दनाक चोट लगने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है, जिससे लकवा हो सकता है। इस तरह की चोट दुर्घटना, गिरने या हिंसक हरकतों के कारण हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी डिमाइलेटिंग बीमारियाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस (MS) एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं के सुरक्षात्मक आवरण पर हमला करती है, जिससे मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। इससे कई तरह के पक्षाघात हो सकते हैं।

मोटर न्यूरोन रोग (एमानडी): मोटर न्यूरोन रोग, जैसे कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस), स्वेच्छिक मांसपेशी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित

ठंड के समय में सबसे अधिक लोगों में लकवा की समस्या देखने के लिए मिलती है। डॉक्टरों का कहना है कि लकवा टेंशन के कारण होता है, जिससे नशे चौक हो जाती है। ऐसे में हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं, तो ठंड के दिनों में आपके खान-पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा।

एक्सपर्ट डॉक्टर बताते हैं कि ठंड के दिनों में यदि कोई भी व्यक्ति अधिक टेंशन ले लेता है, तो उसके कारण नशे चौक हो जाती हैं, जिससे पैरालिसिस होने का डर बना रहता है और अपने खान-पान पर भी आपको विशेष ध्यान देना होता है। अधिक रात में कोई भी ठंडी चीज का सेवन नहीं करें। शरीर का तापमान बना रहे ऐसी चीज खाए और ठंडा खाने से बच्चे और ठंड अधिक पड़ने पर अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप पैरालिसिस के अटैक से बच सकते हैं। 3 महीने में थेरेपी से लकवा ठीक हो जाता है। बालक मार्को का कहना है कि मैंने सबसे पहले लकवा पर ही काम करना शुरू किया था और अभी तक में 8 साल में 5000 से अधिक मरीज ठीक कर चुका हूँ, जिनको 3 महीने में आराम मिल जाता है, लेकिन उनको नियमित

रूप से थेरेपी करना होती। लकवा, एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर के एक हिस्से या अधिकांश भाग में मांसपेशियों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है, इससे प्रभावित लोगों और उनके प्रियजनों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश आती है। चाहे चोट, बीमारी या तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण लकवा का प्रबंधन और ठीक होने का प्रयास अक्सर जटिल और भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। हालाँकि, चिकित्सा विज्ञान और पुनर्वास चिकित्सा में प्रगति लगातार नियंत्रण पाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए रास्ते खोल रही है। यह लेख लकवा के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करता है, इसके कारणों, नवीनतम प्रबंधन रणनीतियों और ठीक होने के





करते हैं। इन न्यूरॉन्स के प्रगतिशील अधरूपतन से मांसपेशियों में कमजोरी और पक्षाघात होता है।

बेल्स पाल्सी: बेल्स पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जो चेहरे की मांसपेशियों में अचानक, अस्थायी कमजोरी या पक्षाघात का कारण बनती है। यह आमतौर पर चेहरे के सिर्फ एक तरफ को प्रभावित करता है और वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है जो चेहरे की तंत्रिका में सूजन का कारण बनता है।

टोड का पक्षाघात: टोड का पक्षाघात एक अस्थायी पक्षाघात है जो दौरे के बाद हो सकता है। यह आमतौर पर शरीर के एक तरफ को प्रभावित करता है और कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक रह सकता है।

टिक पक्षाघात और लाइम रोग: टिक पक्षाघात टिक की कुछ प्रजातियों द्वारा उत्पादित न्यूरोटॉक्सिन के कारण होता है। टिक के काटने से फैलने वाला लाइम रोग तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है और गंभीर मामलों में पक्षाघात का कारण बन सकता है।

स्पाइना बिफिडारु स्पाइना बिफिडा एक जन्मजात स्थिति है जो तब होती है जब मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या इन अंगों के सुरक्षात्मक आवरण ठीक से विकसित नहीं होते हैं। इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग डिग्री का लकवा और अन्य न्यूरोलॉजिकल जटिलताएँ हो सकती हैं।

लकवा के प्रकार

लकवा को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो प्रभावित क्षेत्रों की सीमा और स्थान पर निर्भर करता है। यहाँ लकवा के प्राथमिक प्रकार दिए गए हैं:

1 मोनोप्लेजिया

मोनोप्लेजिया केवल एक अंग को प्रभावित करता है, जैसे कि हाथ या पैर। इस प्रकार का पक्षाघात अक्सर स्थानीय तंत्रिका या मस्तिष्क की चोट का परिणाम होता है, जैसे कि स्ट्रोक या आघात के कारण।

2 हेमिप्लेजिया

हेमिप्लेजिया शरीर के एक तरफ को प्रभावित करता है, आमतौर पर एक ही तरफ के हाथ और पैर को प्रभावित करता है। यह अक्सर स्ट्रोक या दर्दनाक मस्तिष्क चोटों जैसी मस्तिष्क की चोटों के परिणामस्वरूप होता है।

3 पैराप्लेजिया

पैराप्लेजिया शरीर के निचले आधे हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें दोनों पैर शामिल हैं। इस प्रकार का पक्षाघात आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण होता है, विशेष रूप से वक्षीय या काठ के क्षेत्रों में।

4 चतुर्भुज (टेट्राप्लेजिया)

क्वाड्रिप्लेजिया, जिसे टेट्राप्लेजिया के नाम से भी जाना जाता है, सभी चार अंगों और धड़ को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर ग्रीवा (गर्दन) क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के कारण होता है। यह स्थिति चोट के स्तर से नीचे मोटर

और संवेदी कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

5 डिप्लेजिया

डिप्लेजिया मुख्य रूप से शरीर के दोनों तरफ एक ही क्षेत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि दोनों हाथ या दोनों पैर। यह अक्सर सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों में देखा जाता है और जन्मजात मस्तिष्क की चोटों के परिणामस्वरूप हो सकता है।

6 लॉकड-इन सिंड्रोम

लॉकड-इन सिंड्रोम पक्षाघात का एक दुर्लभ और गंभीर रूप है, जिसमें व्यक्ति सचेत और जागरूक तो होता है, लेकिन आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को छोड़कर किसी भी मांसपेशी को नहीं हिला सकता। यह आमतौर पर ब्रेनस्टेम स्ट्रोक या दर्दनाक मस्तिष्क चोटों के कारण होता है।

लकवा शरीर को कैसे प्रभावित करता है?

लकवा शरीर पर व्यापक और गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे विभिन्न कार्य और प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं जिनसे लकवा शरीर को प्रभावित करता है:

वाक् दुर्बलता: पक्षाघात, खासकर अगर यह भाषण में शामिल मांसपेशियों को प्रभावित करता है, तो बोलने में कठिनाई हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप बोलने में कठिनाई, शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलने में परेशानी या बोलने में पूरी तरह से अक्षमता (अफेसिया) हो सकती है। निगलने में कठिनाईरू डिस्फेगिया या निगलने में कठिनाई, गले की मांसपेशियों को प्रभावित करने वाले पक्षाघात वाले व्यक्तियों के लिए एक आम समस्या है। इससे खाने, पीने में समस्या हो सकती है और घुटन या एस्पिरेशननिमोनिया का खतरा बढ़ सकता है।

रक्त प्रवाह और परिसंचरण में व्यवधान: पक्षाघात सामान्य रक्त प्रवाह और परिसंचरण को बाधित कर सकता है, विशेष रूप से प्रभावित अंगों में। इसके परिणामस्वरूप घाव ठीक से नहीं भर पाते, संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है और दबाव के कारण घाव या अल्सर



विकसित हो सकते हैं।

आंतरिक अंगों और ग्रंथियों का खराब कामकाज रू स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो अनैच्छिक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, पक्षाघात से प्रभावित हो सकता है। यह आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के कामकाज को बाधित कर सकता है, जिससे अनियमित हृदय गति, रक्तचाप में उतार-चढ़ाव और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं: लकवा के कारण मांसपेशियों में शोष हो सकता है, जहां मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उपयोग की कमी के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे जोड़ों में सिकुड़न भी हो सकती है, जहां जोड़ सख्त और स्थिर हो जाते हैं। इसके अलावा, हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है, जिससे फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम बढ़ सकता है।

रक्त के थक्कों का विकास: पक्षाघात के कारण गतिहीनता से डीप वेन थ्रोम्बोसिस (क्वज) विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है, जहाँ रक्त के थक्के गहरी नसों में बनते हैं, आमतौर पर पैरों में। ये थक्के फोफेड़ों तक जा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रूप में जाना जाता है।

मूत्र और श्वा मल त्याग पर नियंत्रण खोना: पक्षाघात मूत्राशय और आंत्र को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित कर सकता है, जिससे असंयम या प्रतिधारण

संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप बार-बार मूत्र मार्ग में संक्रमण, गुर्दे की क्षति और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ हो सकती हैं।

व्यवहार और मनोदशा में परिवर्तन: पक्षाघात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे व्यवहार और मनोदशा में परिवर्तन हो सकता है। पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों में अवसाद, चिंता और भावनात्मक संकट आम है, जो उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

इन प्रभावों को समझने से स्थिति को प्रबंधित करने और पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

लकवाग्रस्त हमले के लक्षण और संकेत

—हाथ-पैरों में झुनझुनी, जलन, ठंड या पिन और सुई की अनुभूति
तीव्र तंत्रिका दर्द

- अनैच्छिक रूप से हिलना, मरोड़ना, या मांसपेशियों में ऐंठन
- अंगों का नियंत्रण और समन्वय धीरे-धीरे खत्म होना
- स्पर्श, अत्यधिक दबाव, कंपन आदि की अनुभूति में कमी।
- पैर खींचने जैसी चाल संबंधी असामान्यताएं
- अस्पष्ट, धीमा भाषण
- नजरों की समस्या
- मूत्र या मल त्यागने में कठिनाई होना

उपाय

तत्काल चिकित्सारू यदि स्ट्रोक (लकवा) के लक्षण दिखें, तो तुरंत अस्पताल जाएं पहले 4.5 घंटे (गोल्डन आवर) बहुत महत्वपूर्ण होते हैं

फिजियोथेरेपी: मांसपेशियों की ताकत और गतिशीलता बनाए रखने के लिए व्यायाम व्यावसायिक थेरेपी रोजमर्रा के काम (खाना, कपड़े पहनना) फिर से सीखने में मदद

दवाएं: कारण के आधार पर डॉक्टर मांसपेशियों को आराम देने वाली या खून पतला करने वाली दवाएं दे सकते हैं

सर्जरी: दबाव हटाने या तंत्रिकाओं की मरम्मत के लिए

सहायक उपकरण: चलने-फिरने के लिए व्हीलचेयर, वॉकर, ब्रेसिंग का उपयोग

घरेलू देखभाल (आहार): घर का बना, पौष्टिक भोजन दें तरल पदार्थ, प्रोटीन और पोटेशियम युक्त आहार लें, फास्ट फूड से बचें

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टोर डेस्क.



भारत ने स्कैश वर्ल्ड कप 2025 जीतकर रचा इतिहास

पीएम मोदी ने गौरव का पल बताते हुए टीम इंडिया को बधाई दी



चेन्नई में आयोजित स्कैश वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने टॉप सीड हांगकांग, चीन को 3-0 से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने टीम को बधाई देते हुए इसे गौरव का पल बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एसडीएटी स्कैश वर्ल्ड कप 2025 में इतिहास रचने और अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए भारतीय स्कैश टीम को बहुत-बहुत बधाई! जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह ने जबरदस्त लगन और पक्का इरादा दिखाया है। उनकी सफलता ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। इस जीत से हमारे युवाओं के बीच स्कैश की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। यह भारत का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहला खिताब है। इससे पहले 2023 में भारत को कांस्य पदक मिला था, लेकिन इस बार टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। भारत स्कैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। फाइनल मुकाबला चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेला गया। पहले मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा ने हांगकांग की का यी ली को 3-1 (7-3, 2-7, 7-5, 7-1) से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। 39 साल की जोशना ने अपनी बेहतरीन कोर्टक्राफ्ट और अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। इसके बाद भारत के नंबर-1 पुरुष खिलाड़ी अभय सिंह ने

एलेक्स लाउ को सीधे सेटों में 3-0 (7-1, 7-4, 7-4) से मात देकर स्कोर 2-0 कर दिया। निर्णायक मैच में 17 साल की युवा स्टार अनाहत सिंह ने टोमाटो हो को 3-0 (7-2, 7-2, 7-5) से हराकर जीत पक्की की। अनाहत टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं और उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। वेलवन सेंथिल कुमार भी टीम का हिस्सा थे, हालांकि फाइनल में उनकी जरूरत नहीं पड़ी। टूर्नामेंट के सफर में भारत ने ग्रुप स्टेज में स्विट्जरलैंड और ब्राजील को 4-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 और सेमीफाइनल में दो बार के डिफेंडिंग चौपियन मिश्र को 3-0 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। पूरी टीम ने लगन, इरादा और टीमवर्क का बेहतरीन नमूना पेश किया।

स्कैश विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को खेल मंत्री ने किया सम्मानित। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक स्कैश विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह की मिश्रित टीम ने पिछले चेन्नई में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा। इस जीत के साथ भारत ने अपना पहला स्कैश विश्व कप खिताब अपने नाम किया। टीम ने 2023 संस्करण में जीते गए कांस्य पदक से बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराया और स्कैश विश्व कप जीतने वाला चौथा देश बन गया। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिश्र जैसे दिग्गज देशों की सूची में शामिल हो गया। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए डॉ. मांडविया ने इसे "भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का क्षण" बताया। उन्होंने कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हाल के समय में विभिन्न खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि अपनी धरती पर विश्व कप जीतना और पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच न हारना टीम की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। भारतीय स्कैश खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोजियम स्कीम (टॉप्स) के तहत मिले सहयोग से भी लाभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय अनुभव,





विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रदर्शन सुधार से जुड़े सुझावों ने खिलाड़ियों की तैयारी को मजबूत किया है। युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इस सफलता का श्रेय चेन्नई के दर्शकों के समर्थन को दिया। 17 वर्षीय अनाहत ने कहा कि वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ विश्व कप खेलना उनके लिए एक बेहतरीन सीखने का अनुभव रहा। विश्व कप जीत के बाद भारतीय टीम की नजर अब एशियाई खेल 2026 और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर है, जहां स्ववैश पहली बार शामिल होगा। अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने कहा कि इस जीत से आगामी एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने भारतीय स्ववैश टीम को विश्व कप जीत पर बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एसडीएटी स्ववैश विश्व कप 2025 में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय स्ववैश टीम को आज बधाई दी। मा. 'दी ने जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने देश को अपार गौरव दिलाया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय खेलों की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत देश भर के असंख्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और भारत के युवाओं में स्ववैश की लोकप्रियता को और बढ़ाएगी। मोदी ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि एसडीएटी स्ववैश विश्व कप 2025 में इतिहास रचते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने के लिए भारतीय स्ववैश टीम को हार्दिक बधाई। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह,

वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह ने जबरदस्त समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। उनकी सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत हमारे युवाओं के बीच स्ववैश की लोकप्रियता को भी बढ़ाएगी।

पृष्ठभूमि और संदर्भ

स्ववैश वर्ल्ड कप एक अंतरराष्ट्रीय मिक्सड-टीम टूर्नामेंट है, जिसमें प्रत्येक देश की चार सदस्यीय टीम होती है—दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ी। इस टूर्नामेंट में 2023 में लागू की गई एक नई और तेज स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे मैच अधिक रोमांचक, तीव्र और दर्शकों के अनुकूल बन जाते हैं। भारत द्वारा तीसरी बार मेजबानी किया जाना यह दर्शाता है कि देश में स्ववैश की लोकप्रियता बढ़ रही है, रैकेट खेलों को मजबूत प्रशासनिक समर्थन मिल रहा है और चेन्नई के पास शानदार आयोजन क्षमता के साथ उच्च स्तरीय सुविधाएँ मौजूद हैं। यह आया। 'जन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल चक्रों से पहले स्ववैश की दृश्यता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। प्रत्येक टीम में दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ी शामिल होंगे। मैचों में तेज-गति वाले पहले 7 अंक वाले गेम खेले जाएंगे, और 6वें पर सडन डेथ (लागू होगी, जिससे हर मुकाबला रोमांचक और अप्रत्याशित बन जाता है।

एक भी मैच नहीं हारी टीम इंडिया

सेकेंड सीड इंडियन स्ववैश टीम ने खिताब तक पहुंचने के रास्ते में अपना एक भी मैच नहीं हारा। ग्रुप स्टेज के मैचों में स्विट्जरलैंड और ब्राजील को 4-0 के एक जैसे अंतर से हराने के बाद, भारत ने

क्वार्टर और सेमीफाइनल में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और 2 बार के चौपियन मिश्र को 3-0 से हराया, और मिक्सड-टीम स्ववैश इवेंट में खिताब के लिए मुकाबला पक्का किया। रविवार 14 दिसंबर 2025 को सीनियर प्लेयर जोशना चिनप्पा, जो पीएसए रैंकिंग में 79वें नंबर पर हैं, उन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दी, जब उन्होंने शुरुआती महिला सिंगल्स मैच में दुनिया की नंबर 37 ली का यी को 3-1 (7-3, 2-7, 7-5, 7-1) से हराया।

अभय और अनाहत भी जीते

एशियन गेम्स के मेडलिस्ट अभय सिंह, जो दुनिया के 29वें नंबर के भारत के बेस्ट रैंक वाले मंस सिंगल्स प्लेयर हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 42वें नंबर के एलेक्स लाउ को 19 मिनट में 3-0 (7-1, 7-4, 7-4) से हराकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। जीत और ऐतिहासिक खिताब पक्का करने के लिए, 17 साल की अनाहत सिंह आगे आई और प्रेशर को शानदार ढंग से संभाला।

3-0 से बने चौपियन

दुनिया की नंबर 31 टोमेटो हो के खिलाफ, 28वें नंबर की भारतीय स्ववैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और तीसरे मैच में 3-0 (7-2, 7-2, 7-5) से जीत हासिल की, जिससे ये कफर्म हो गया कि भारत को फाइनल मैच में हेनरी लेउंग के खिलाफ पुरुष सिंगल्स नेशनल चौपियन वेलवन सेंथिलकुमार को कोर्ट में उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। अभय सिंह ने कहा, 'एक अविश्वसनीय शाम, मैं और क्या कह सकता हूँ? मुझे कुछ सच में दिग्गज टीम के साथियों के साथ ऐसा करने का सौभाग्य मिला और साल का क्या शानदार अंत और क्या शानदार हफ्ता रहा।'

ओलंपिक मेडल के लिए जगी उम्मीदें

इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिश्र के बाद स्ववैश वर्ल्ड कप के 5 एडिशन में खिताब जीतने वाला चौथा देश बन गया। ऐसा लगातार तीसरी बार था जब ये मीट चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया। इस जीत के साथ ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। क्योंकि 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक में स्ववैश गेम को पहली बार दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल किया गया है।

प्रस्तुति-प्राइम स्पेक्टोर डेस्क.

फिल्मों में एंग्री मेन, पर्दे से क्यों लापता लेडीज



भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जैसे अपने जाने-पहचाने मैदान में खेलने के लिए वापस पहुंच गई. उससे पहले वाले साल में महिला केंद्रित कहानियों ने थोड़े समय के लिए भारत की वैश्विक सिनेमाई छवि को बदला था... वाहवाही बटोरी थी और नए लोगों का ध्यान खींचा था. लेकिन पिछले साल बॉलीवुड की हिंसक, पुरुष-प्रधान एक्शन थ्रिलर फिल्मों घरेलू बॉक्स ऑफिस और सांस्कृतिक चर्चाओं पर छा गई.

2025 के आखिरी हफ्तों में भारतीय सोशल मीडिया पर बस एक ही फिल्म की चर्चा थी, श्चुधरंधर. यह भारत-पाकिस्तान तनाव की पृष्ठभूमि पर बनी एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है. हिंसा को खुलकर दिखाने वाली और अपराध की दुनिया की राजनीति से भरी यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट बनी. इसके साथ ही यह आक्रामक, अति-पुरुषवादी फिल्मों की उस श्रृंखला में शामिल हो गई जो बहुत लोकप्रिय रही हैं.

यह रुझान 2024 से पूरी तरह अलग था. उस साल महिलाओं की बनाई कई फिल्मों, जैसे कि पायल कपाड़िया की शॉल वी इमैजिन ऐज लाइट्स, शुचि तलाठी की शर्ल्स विल बी गर्ल्स और किरण राव की 'लापता लेडीज', ने दुनिया का ध्यान खींचा था और सराहना पाई थी.

फिल्म समीक्षक मयंक शेखर कहते हैं, 2024 ने साबित किया कि भारतीय महिला फिल्मकार हाशिए की नहीं, बल्कि दुनिया की अगुवाई करने वाली आवाजें हैं. वह इसे कोई अस्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि एक निर्णायक पल मानते हैं.

उम्मीद थी कि महिलाओं की कहानियों पर आधारित और गहरी, परतदार फिल्मों संख्या

और लोकप्रियता दोनों में बढ़ेगी. लेकिन 2025 में टॉप 10 बॉक्स ऑफिस हिट्स में असाधारण, अति-पुरुषवादी हीरो छाए रहे. वैसे इनमें से पांच फिल्मों बॉलीवुड की थीं जो महामारी के बाद अब तक संघर्ष कर रही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए थोड़ी राहत की बात थी. इनमें 'छावा' जैसी ऐतिहासिक और 'वॉर 2' जैसी एक्शन फिल्मों शामिल थीं. इस सूची में महिला-प्रधान सिर्फ एक फिल्म थी, मलयालम भाषा की सुपरहीरो फिल्म 'लोकाह'.

मर्दानगी का भाव हावी रहा

सिर्फ एक्शन थ्रिलर ही नहीं, रोमांटिक ब्लॉकबस्टर श्रेंयाराश भी एक परेशान पुरुष रॉकस्टार की कहानी थी, जो अंत में अपनी अल्जाइमर से जूझ रही पार्टनर को 'संभालता' है. हां तक कि 'कांतारा: चैप्टर 1' (कन्नड़) और 'महावतार नरसिंह' (कई भाषाओं में डब) जैसी पौराणिक फिल्मों भी पारंपरिक पुरुष वीरता को और मजबूत करती दिखीं. साल की सबसे चर्चित फिल्मों में पुरुषों की पीड़ा, ताकत और बदले के भाव पूरे जोर-शोर से हावी रहे.

टॉप 10 फिल्मों में सबसे ज्यादा बहस जिस फिल्म को लेकर रही वह थी 'तेरे इश्क में'. इसमें गुरसैल और अस्थिर पुरुष किरदार हैं, और एक महत्वाकांक्षी महिला, जिसकी आकांक्षाओं को आदमी के सनकभरे प्यार का ग्रहण लग जाता है. दमनकारी पुरुषवादी सोच को रूमानी बनाकर पेश करने के आरोपों के बावजूद, यह फिल्म अभिनेता धनुष की सबसे बड़ी हिंदी हिट साबित हुई. इसने दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये से ज्यादा

कमाए.

एक और चौंकाने वाली हिट रही, 'एक दीवाने की दीवानियत'. यह छोटे बजट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी. एक रिव्यू के अनुसार इसका हीरो एक सनकी प्रेमी है, जो ना सुनने को तैयार ही नहीं.

किंग्स कॉलेज लंदन में परफॉर्मिंग आर्ट्स की सीनियर लेक्चरर प्रियंका बसु कहती हैं कि 2024 ने संभावनाओं की एक झलक दिखाई थी. वह कहती हैं कि हिंदी सिनेमा ने ऐतिहासिक रूप से महिला नायिकाओं को हाशिए पर रखा है. पुरुष-प्रधान इंडस्ट्री में लंबे समय से कास्टिंग, पेमेंट और अवसरों में गहरी असमानताएं रही हैं.

उनका कहना है, सिर्फ एक साल में यह सब बदलना संभव नहीं है. हमें ऐसे और साल चाहिए, ऐसी और कहानियां चाहिए जिनमें महिलाएं केंद्र में हों.

भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड की मर्दाना हीरो वाली दीवानगी 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की शंघी यंग मैनश वाली छवि से शुरू हुई थी. यहां तक कि शाहरुख खान का रोमांटिक दौर भी बस एक छोटा सा बदलाव था, जिसे छोड़कर उन्होंने बाद में पठान और जवान जैसी एक्शन-प्रधान ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करना पसंद किया.

ओटीटी में भी घट गई महिला-प्रधान कहानियां

कभी माना जाता था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों में महिलाओं की कहानियों को केंद्र में रखकर कही गई कहानियां चल सकती हैं लेकिन यह ट्रेंड अब वहां भी पहुंच गया है.

मीडिया रिसर्च कंपनी ऑरमैक्स की एक ताजा रिपोर्ट में 338 हिंदी शोज का विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि अब एक्शन और क्राइम थ्रिलर (ज्यादातर पुरुष-प्रधान) की 43% हिस्सेदारी है. महिला-प्रधान कहानियां जो 2022 में 31% थीं, 2025 में घटकर सिर्फ 12% रह गईं.

मयंक शेखर कहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्मों ने बॉक्स ऑफिस की राह पर चलना शुरू कर दिया. अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों सिनेमा में चल रहे ट्रेंड्स को चुनौती देने के बजाय उनकी नकल कर रहे हैं.

लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि यह बदलाव इंडस्ट्री की रचनात्मक गिरावट नहीं,



बल्कि दर्शकों की मांग को दर्शाता है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं, भारतीय फिल्मों परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान रही हैं, लेकिन हमारे पास शमदर इंडिया और 'पाकीजा' जैसी महिला-केंद्रित क्लासिक्स भी रही हैं।

उनका कहना है कि दमनकारी पुरुषवादी सोच के आरोप कुछ गिने-चुने आलोचक ही लगाते हैं और इनसे फिल्मों का भाग्य तय नहीं होता। वह आगे कहते हैं, अंत में जिस बात से सचमुच में असर पड़ता है वह सिर्फ दर्शकों का फैसला होता है।

लेकिन अनु सिंह चौधरी का मानना है कि सब कुछ दर्शकों की पसंद पर डाल देना बहुत सरलीकरण है। अनु, नेटपिलक्स थ्रिलर शदिल्ली क्राइम 3 की सह-लेखिका हैं। इस सीरीज में महिलाओं की तस्करी के मुद्दे को नारीवादी नजरिए से दिखाया गया है।

वह कहती हैं, झड़ना कहानी वाली ब्लॉकबस्टर लंबे समय से इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वे एक ऐसे समाज को दिखाती हैं जो हमेशा से पितृसत्तात्मक और पुरुष-प्रधान रहा है। क्या यह रातों-रात बदल जाएगा? नहीं। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया का ढांचा बदलता है, हमारी फिल्मों भी बदलेंगी।

इसके साथ ही आर्थिक हकीकत भी है। निर्माता, वितरक और प्रदर्शक तय करते हैं कि किसी फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी, कितना प्रचार होगा और दर्शकों तक उसकी

कितनी पहुंच होगी। और यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष स्टार बॉक्स ऑफिस पर कितना भरोसेमंद है या कितनी कमाई कराने वाला माना जाता है। स्वतंत्र और महिला-प्रधान फिल्मों के लिए लड़ाई मुश्किल होती है, खासकर तब जब उनमें बड़े सितारे न हों।

इंडस्ट्री से है उम्मीद

छपाक और मार्गरीटा विद ए स्ट्रॉ जैसी



महिला-प्रधान फिल्मों की स्क्रीनराइट अतीका चौहान, कहती हैं कि आजकल की फिल्मों दिखावटी और अतिरंजित स्त्री-विरोध के दौर से गुजर रही हैं। उनका मानना है कि इसकी कुछ वजह 2017-19 के 'मी टू' आंदोलन के दौरान महिलाओं द्वारा मांगी गई जवाबदेही की प्रतिक्रिया है।



शमी टूश आंदोलन ने फिल्म इंडस्ट्री में फैले व्यापक शोषण को उजागर किया था, लेकिन उसका असर असमान रहा। जिन पर आरोप लगे उनमें से कुछ को अस्थायी झटके लगे, लेकिन ज्यादातर वापस काम पर लौट आए और सत्ता का ढांचा वैसा ही बना रहा। अती. का चौहान कहती हैं, जब तक ये अति-मद. निपन वाली फिल्मों पैसा कमा रही हैं, कुछ नहीं बदलने जा रहा।

लेकिन हमेशा की तरह उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं, जो ज्यादातर छोटी, क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री और स्वतंत्र फिल्मकारों की तरफ से आ रही हैं।

अनु सिंह चौधरी ध्यान दिलाती हैं कि भारत में नई पीढ़ी के स्वतंत्र फिल्मकार बदलचस्प और व्यवहारिक सिनेमा बना रहे हैं, न कि सिर्फ प्जनता को लुभाने वाला मनोरंजन।

शसबर बोंडाश और शसॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जैसी भारतीय फिल्मों भी हैं जो सामा. जिक और राजनीतिक परतों में गहराई से उतरकर रिश्तों की संवेदनशील कहानिय. ि सनाती हैं। तेलग फिल्म शद गर्लफरेडश

एक महिला की कहानी थी, जो जहरबुझे रिश्ते से खुद को आजाद करना सीखती है। वहीं तमिल फिल्म शबैड गर्लश को महिला दृष्टिकोण से दिखाए गए परिपक्व होने के सफल ड्रामा के रूप में सराहा गया।

मलयालम फिल्म फेमिनिची फातिमा, जिसमें फेमिनिची सोशल मीडिया पर फेमिनिस्ट का बिगड़ा हुआ रूप है, ने मजाक के जरिए एक मुस्लिम गृहिणी की पितृसत्ता के खिलाफ शांत बगावत को दिखाया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 'द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली' को आधु. निक मुस्लिम महिलाओं की रोजमर्रा की जहोजहद और जटिलताओं को बारीकी से पकड़ने के लिए सराहा गया। चौधरी कहती हैं, यह शांति के साथ चल रहा एक आंदोलन है, जो हाशिए से काम कर रहा है। और यह गायब होने वाला नहीं है। Courtesy www.bbc.com

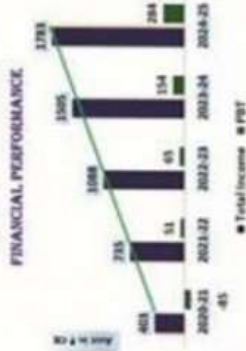


HINDUSTAN SHIPYARD LIMITED

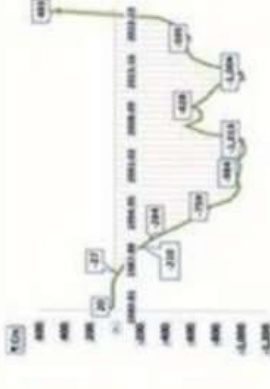
(GoI Undertaking, Ministry of Defence) A MINIRATNA COMPANY

Celebrating 85 years of Shipbuilding Excellence

DRIVING GROWTH @ HSL



POSITIVE NETWORK @ HSL



HSL has transformed from negative to positive net worth after 40 years and has recently been granted Miniratna status. HSLs future vision including development of Green Tugs (Electric & Hydrogen powered) is aimed at reducing carbon emissions. HSL is striving to promote self-reliance, innovation & maritime development contributing to Swarna Andhra & Viksit Bharat thereby playing a key role in developing Vizag as a maritime Hub.

India's largest Defence shipbuilding yard Hindustan Shipyard Limited, recently celebrated 85 years of maritime excellence on June 21st 2025. HSL has come a long way, having started way back in 1941 by the legendary Seth Walchand Hirachand

HSL has faced testing times over the years, from being India's first greenfield shipyard to experiencing dismal orders and mounting losses. However today HSL is a rejuvenated shipyard, one that is buzzing with enthusiasm, energetic & motivated employees coupled with a thriving and rapidly growing order book.

Timely delivery, customer satisfaction and customer is King attitude is today widely witnessed and felt at this landmark shipyard on the east coast of India.

HSL AT WORK



Powering the Green Vessel
Revolution with Hydrogen Fuel Cells



Driving Aatmanirbharta through
Fleet Support Ships Mega Project



Hub for thriving Ship & Submarine
Refit Ecosystem on the East Coast



www.hslvizag.in



twitter.com/CMD_HSL



linkedin.com/in/hindustanshipyard



instagram.com/hindustanshipyard



facebook.com/hslvizag



With a legacy of 45+ years, NCC Limited stands among India's most trusted infrastructure conglomerates, delivering excellence across Buildings, Transportation, Water, Irrigation, Mining, Electrical (T&D), and Railways. From roads to digital highways, airports to power networks, NCC continues to shape India's growth story through innovation, sustainability, and inclusive development for a Viksit Bharat.